

भुगतान संतुलन

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक गतिविधि द्वारा संचालित विश्व अर्थव्यवस्था संकट से धीरे-धीरे उबर रही है। तथापि, जोखिम बने रहेंगे, चूंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च सार्वजनिक ऋण तथा बेरोजगारी का सामना कर रही हैं और कुल मांग में शिथिलता का अनुभव किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप विकास में कमी आयी है। बाह्य यूरो-क्षेत्र देशों में सरकारी ऋण संकट अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी का प्रवाह, तेल तथा कृषि सम्बन्धी कीमतों में बढ़ोतरी स्फीतिकारी दबावों में तेजी ला रही हैं जो उदीयमान वैश्विक बहाली को प्रभावित कर सकती है। इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरन्तर सुधार प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रही है और संकट पूर्व के विकास रास्ते की दिशा में बढ़ रही है। तथापि, मौजूदा लेखा घाटा तीव्र आयात मांग तथा कम मात्रा में अदृश्य अधिशेष के कारण बढ़ा है। इसे मुख्यतः सापेक्षतया उच्च पूंजी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है जिससे प्रारक्षित निधियों में मामूली संचय हुआ है। तथापि, कई चुनौतियां हैं जिनमें विदेशी संस्थागत निवेश का अनिश्चित स्वरूप निहित है और जिसे पूंजी प्रवाहों में बढ़ोतरी तथा विपर्यय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मंदी तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आगे मंदी के जोखिम में देखा जा सकता है जिसके निर्यात को प्रभावित करने के साथ भुगतान पर दबाव बनाए रखने की आशंका है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

6.2 विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं जो मुख्यतः उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आए तीव्र विकास के कारण संभव हुआ है। उन्नत देश हालांकि बैंकों, कारपोरेट इकाइयों तथा वैयक्तिकों के अनियंत्रण के साथ बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटा तथा उच्च लोक ऋण और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जो कुल मांग पर प्रभाव डाल रहा है और जिससे सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंच रही है।

6.3 बाह्य यूरो जोन अर्थ-व्यवस्थाओं में सरकारी ऋण संकट का जोखिम और इस आशंका ने कि यह बड़ी मात्रा में सरकारी ऋण प्रकटन सहित बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्रों में फैल सकता है, बाजारों में अव्यवस्था फैलाई है। यूरो पर संभावित प्रभाव तथा वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाला संभावित जोखिम पुनर्संरचना के माध्यम से प्रभावित देशों के सरकारी ऋण पर पड़ने वाले प्रभाव से बचने के प्रयासों हेतु उत्तरदायी है।

6.4 निवेशकों के प्रभावित होने से यूरोपीय वित्तीय स्थायित्व सुविधा (ईएफएसएफ) और अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि

(आईएमएफ) के तत्वावधान में आयरलैंड राहत पैकेज ने बाजारों पर अपेक्षित स्थिरीकरण प्रभाव पैदा नहीं किया। कई लोगों को यह भी आशंका है कि स्पेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तथा अन्य यूरो जोन देशों में संकट फैलने की स्थिति में इटली और बेल्जियम जैसे उच्च श्रेणी देशों को ईपीएसएफ बड़ी मात्रा में राहत प्रदान करने वाला नहीं होगा। यह भी जोखिम है कि यह संकट निवेशकों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार में विलंब हो सकता है।

6.5 निवेशकों में हताशा सरकारी, बैंकों तथा कारपोरेट ऋणों की उच्च पुनर्वित्त आवश्यकता की वजह से है और यह भी आशंका है कि परिपक्वता देयताओं की पूर्ति हेतु बाजार में पर्याप्त नकदी नहीं होगी। यह भी आशंका है कि सरकार के प्रोत्साहन प्रयास वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित किए बिना लोक ऋण के समक्ष संकट को सामान्यतः उच्च निजी ऋणों से प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं।

6.6 निवेशकों में अनिश्चितता मुद्रा बाजारों में उच्च घट-बढ़ के रूप में दिखायी देती है। इसके अलावा, कोई भी करेंसी सुरक्षा

प्रदान नहीं कर रही है, इसलिए कई निवेशक पण्यों का आश्रय ले रहे हैं और उन्हें विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) जैसे निवेशक अनुकूल लिखतों, पण्य सूचकों से सहायता मिल रही है और वे वायदा बाजार में अपने को सहज महसूस कर रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं से मांग बढ़ने के साथ ही यह प्रवृत्ति स्वर्ण, तेल, धातु तथा खाद्यान्न जैसे नाशावान उत्पादों में दिखाई दे रही है। तथापि, तेल तथा खाद्यान्न जैसे जिनसों की कीमतों में बढ़ोत्तरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन पर दबाव बना रही है और मूल्य बढ़ोत्तरी में योगदान देकर उनकी विकास संभावनाओं को प्रभावित कर रही है।

6.7 ब्याज विभेदकों (वाहक व्यापार), उच्च स्टॉक बाजार आय तथा बेहतर विकास संभावनाओं का लाभ लेने हेतु उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह में तेजी अनिश्चित विकास संभावनाओं का एक अन्य परिणाम है और यह उन्नत देशों में निम्न ब्याज माहौल पैदा करता है। तथापि, पूंजी अधिक्व शेयर बाजार/रीयल एस्टेट में अनिश्चितता पैदा कर रहा है और स्थानीय मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। अधिक नकदी के साथ स्फीतिकारी दबावों को सहायता मिल रही है।

6.8 इसके साथ ही आर्थिक थ्योरी महत्वपूर्ण दौर में है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं को महत्व न दिए जाने तथा मूल्यों को प्रभावी संकेतक मैकेनिज्म के तौर पर न देखे जाने से स्व-सुधार प्रक्रिया में विश्वास, बाजार मैकेनिज्म में पड़ने वाले अवश्यम्भावी प्रभाव में सहायक है। घाटा वित्त पोषण की किंस अवधारणा और उच्च सरकारी व्यय पर भी शंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि

यह बेरोजगारी और उन्नत देशों में कुल मांग समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किए बिना लोक ऋण की दिशा की तरफ जाता है।

6.9 कार्यक्षम बाजार परिकल्पना जैसे कुछ मुख्य वित्तीय बाजार सिद्धांतों जो बाजार का मुख्य सहारा रही हैं, के प्रति शंकाएं रही हैं। सरकारी ऋण के जोखिम मुक्त स्वरूप पर आधारित सिद्धांत जो वित्तीय बाजार मॉडलिंग का आधार रही हैं, बाह्य यूरो जोन देशों में चूक/पुनर्संरचना के जोखिम के कारण आलोचना के घेरे में आए हैं और कई उन्नत देशों में अस्थायी स्तरों पर लोक ऋण की दिशा में बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप, कई शीर्षस्थ कारपोरेट इकाइयों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बांडों की कीमत कुछ यूरो जोन देशों की तुलना में अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी दिखाई दे रही है।

6.10 आगामी परिप्रेक्ष्य में, अर्थशास्त्र तथा वित्त दोनों पर नए सिरे से विचार करने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम, यह स्वीकार किया जा रहा है कि बाजार चढ़ाव-उतार की प्रक्रिया अधीन हैं जो ऋण चालित परिसम्पत्ति मूल्य अस्थिरता की वजह से गंभीर मोड़ ले सकता है और जिसे सकारात्मक फीडबैक लूप द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए प्रतिक्रम्य उपाय तथा समय की अनुकूलता आवश्यक है। दूसरा, अर्थशास्त्र तथा वित्त के साथ व्यवहार्यात्मक कारकों के समीकरण पर नए सिरे से जोर दिए जाने की आवश्यकता है ताकि सिद्धांत को वास्तविक विश्व परिस्थिति के और निकट लाया जा सके।

बाक्स 6.1 : बिक्र अध्ययन रिपोर्ट

बिक्र शब्द ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी गोल्डमैन साक्स ने 2001 में 'बिल्डिंग बैटर ग्लोबल इकोमिक्स बिक्र्स' नामक दस्तावेज में कल्पना की थी जो चार सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भावी विकास सम्भावनाओं पर गौर करती है। बिक्र देश चूँकि अब विश्व पटल पर प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। बिक्र राष्ट्रध्यक्ष तथा वित्त मंत्री बिक्र देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु समय-समय पर बैठकें भी करते हैं।

4 सितम्बर, 2009 को लन्दन में बिक्र वित्त मंत्रियों तथा सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान, विश्व अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं की जांच करने तथा संकट पश्च विश्व में बिक्र देशों की भूमिका का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। बैठक की विज्ञप्ति में यह भी नोट किया गया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने विश्व अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकट से बचाने हेतु व्यापार, ऋण प्रवाह तथा मांग में व्यापक गिरावट के प्रभाव को कम करने में योग दिया है।

विश्व पटल पर बिक्र अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते महत्व और आगामी वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संयुक्त अध्ययन का उद्देश्य पारस्परिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा संयुक्त रूप से वैश्विक आर्थिक सुधार हेतु बिक्र देशों के मध्य सहयोग के सम्भाव्य क्षेत्रों का पता लगाना था।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारत अध्ययन परियोजना तैयार करेगा। प्रत्येक चार देशों से सफलतापूर्वक अध्ययन हेतु सरकारी/सेन्ट्रल बैंक के विशेषज्ञों को लेकर एक कार्य दल बनाया गया। कई क्षेत्रों में प्रत्येक बिक्र देशों की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रियाओं और अनुभवों का लाभ उठाकर इस दल के सदस्य स्वयं आपस में सहयोग करते रहे हैं। सितम्बर 2010 में नई दिल्ली में इस कार्य दल की पहली बैठक हुई थी और जिसमें सभी चार बिक्र देशों के भागीदारों ने भाग लिया था। इस बैठक में रिपोर्ट के कई चरणों को अन्तिम रूप दिया गया जिसमें सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान तथा बिक्र देशों के समक्ष चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान जैसे मुद्दे शामिल थे और मसौदा अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी हेतु समय अनुसूची भी थी।

रिपोर्ट का पहला मसौदा भारतीय दल द्वारा तैयार किया गया और यह मूल्यांकन तथा सूचनाओं हेतु बिक्र देशों के मध्य परिचालन अधीन है।

6.11 तीसरा, यह मान्यता निरन्तर जोर पकड़ रही है कि बाजारों के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु एक विवेकसम्मत तथा पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इसके साथ ही, विभिन्न देशों के विनियामक एजेंसियों के बीच समन्वयन होना जरूरी है ताकि विनियामक विवाचन के जोखिम को कम किया जा सके। चौथा, टॉप-डाउन एप्रोच वाले वृहद् विवेकसम्मत विनियम नई नीति बजवर्ड है जिसे हाल में घोषित बेसल-III नियमों में स्पष्ट किया गया है और जिसमें व्यापक आर्थिक स्थायित्व का सुनिश्चय करने हेतु बैंक पूंजी पर प्रति चक्रीय बफर तथा प्रतिबंधों को लगाना शामिल है।

6.12 ऐसी अनिश्चितता तथा स्थिरीकरण के प्रयासों की पृष्ठभूमि में अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाएं उच्च विकास दर के साथ निरन्तर अच्छा निष्पादन कर रही हैं जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ पृथक् उपायों का संकेत करती हैं। यह मुख्यतः इस कारण है: (i) कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं 1980 तथा 1990 के दशक में उत्पन्न संकटों के बाद आत्म निरीक्षण तथा सुधार के दौर से गुजरी हैं जिस कारण घरेलू तथा लोक ऋण का स्तर नीचे आया है, सार्वजनिक व्यय को सही दिशा में मोड़ा गया तथा संस्था निर्माण भी हुआ; (ii) उभरती अर्थव्यवस्थाओं का न्यूनतम प्रकटन रहा है तो संकट के प्रादुर्भाव तथा प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं; और जिन्होंने संपार्श्विक भरण देयताएं (सीडीओ) और ऋण चूक जैसे वित्तीय अभिनवों के संकट के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिसका उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर सीमित प्रभाव पड़ा है।

6.13 भारत का सौभाग्य रहा कि (क) उसका विकास मुख्यतः घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर है; (ख) पूंजी लेखा उदारीकरण से सम्बद्ध सुविचारित दृष्टिकोण से व्यापक विवाचन रुका और जिससे पूंजी प्रवाह में तेजी तथा विपर्यय हुआ; (ग) बैंकों के कठोर पर्यवेक्षण ने विदेशों में परिसम्पत्तियों का प्रकटन रोका तथा रीयल एस्टेट को अत्यधिक ऋण देना सम्भव हुआ जिसने बैंकों को रीयल एस्टेट की अस्थिरता के खतरों से बचाया; (घ) ऋण चूक अदला-बदली जैसे ऋण व्युत्पन्न लिखतों ने जिन्होंने संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अभी बाजार में प्रारम्भ किया जाना है।

भुगतान संतुलन

6.14 भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता, पूंजी खाता, भूल-चूक और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन शामिल है। बीओपी के चालू लेखे के तहत लेन-देनों को पण्य (निर्यात तथा आयात) और अदृश्य लेखों में वर्गीकृत किया जाता है। अदृश्य लेखों को पुनः तीन वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात् (क) सेवाएं-यातायात, परिवहन, बीमा, अन्यत्र असम्मिलित सरकार

(जीएनआईआई), तथा विविध जिसमें बाद में संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, रायल्टी, प्रबन्ध तथा कारोबारी सेवाओं को शामिल किया गया है, (ख) आय और (ग) अन्तरण (अनुदान, उपहार, विप्रेषण आदि) जिनका कोई मुआवजा नहीं है।

6.15 पूंजी लेखे के तहत, पूंजी अन्तर्प्रवाह को लिखत (ऋण अथवा इक्विटी) और परिपक्वता (अल्प अथवा दीर्घावधि) द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजी लेखे के मुख्य संघटकों में विदेशी निवेश, ऋण तथा बैंकिंग पूंजी शामिल है। विदेशी निवेश में विदेशी प्रत्यक्ष और (एफडीआई) तथा पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) निवेश एवं अमरीकी निक्षेपागार रसीद/वैश्विक निक्षेपागार रसीद (एडीआर/जीडीआर) ऋण भिन्न देयताओं को संकलित करता है, जबकि ऋण (विदेशी सहायता, विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा व्यापार ऋण) तथा अप्रवासी भारतीय जमा राशियों सहित बैंकिंग पूंजी ऋण देयताएं हैं।

6.16 वर्ष 2009-10 के दौरान बीओपी घटनाक्रम संकेत देते हैं कि निम्न व्यापार घाटे के बावजूद चालू लेखा घाटा अदृश्य प्राप्तियों में मंदी के कारण विस्तृत हुआ। पूंजी प्रवाह में भी तीव्र बढ़ोतरी हुई जिससे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का संचयन हुआ। 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत का मौजूदा लेखा घाटा 2008-09 में 2.3 प्रतिशत की तुलना में है तथापि, यह धारणीय सीमा तक बना रहा। निवल पूंजी प्रवाह में 2008-09 में 0.5 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में सघट का 3.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। इसकी वजह से बीओपी आधार पर विदेशी प्रारक्षित निधियों में 13.4 बिलियन अमरीकी डालर का निवल संचय हुआ जो 2008-09 में 20.1 बिलियन अमरीकी डालर के निवल बहिर्प्रवाह की तुलना में था।

6.17 2009-10 में बीओपी घटनाक्रम ने आर्थिक सुधार हेतु कई अवसर प्रदान किए। कमजोर वैश्विक मांग के प्रत्युत्तर में वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में गिरावट ने समग्र सघट विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। तथापि, उच्च चालू लेखा खाता विदेशी पूंजी के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग की दिशा में गया। इसमें विदेशी पूंजी द्वारा वित्तपोषित उच्च निवेश गतिविधि शामिल है जिसे विकास में ठोस बहाली हेतु आंशिक रूप से सहायक माना गया। विदेशी मांग, अन्तरराष्ट्रीय तेल तथा जिंस मूल्यों पूंजी प्रवाह का पैटर्न, जैसे बीओपी लेन-देनों के मुख्य निर्धारक तत्व और मुद्रा दर में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। निर्यात में बढ़ोतरी तथा पूंजी प्रवाह में बहाली से विदेशी क्षेत्र की चिंताएं 2009-10 में धीरे-धीरे घटती गयीं।

6.18 उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2010-11 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर 2010) के दौरान बीओपी घटनाक्रमों की मुख्य विशेषताएं यह रही कि 2009-10 की पहली छमाही

सारणी 6.1 : भुगतान संतुलन : सारांश		(मिलियन अमरीकी डालर)						
क्र.स.	मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 एच1 (अप्रैल- सित्त. 2009) ^{आ.स.}	2010-11 एच1 (अप्रैल- सित्त. 2010) ^{आ.स.}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I चालू खाता								
1.	निर्यात	1,05,152	1,28,888	1,66,162	1,89,001	1,82,235	82569	110518
2.	आयात	1,57,056	1,90,670	2,57,629	3,08,521	3,00,609	138419	177457
3.	व्यापार संतुलन	-51,904	-61,782	-91,467	-1,19,520	-1,18,374	-55850	-66939
4.	अदृश्य (निवल)	42,002	52,217	75,731	91,605	79991	42511	39058
क.	कारक भिन्न सेवाएं	23,170	29,469	38,853	53,916	35726	19098	19510
ख.	आय	-5,855	-7,331	-5,068	-7,110	-8040	-3279	-6509
ग.	अन्तरण	24,687	30,079	41,945	44,798	52,305	26,692	26,057
5.	वस्तु तथा सेवा शेष	-28,734	-32,313	-52,614	-65,604	-82,648	-36,752	-47,429
6.	चालू खाता शेष	-9,902	-9,565	-15,737	-27,915	-38,383	-13,339	-27,881
II. पूंजी लेखा								
1		25,470	45,203	1,06,585	6,768	53,397	22,964	36,661
I.	विदेशी सहायता (निवल)	1,702	1,775	2,114	2441	2893	1023	2993
II.	विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	2,508	16,103	22,609	7,862	2,808	728	5,974
III.	अल्पवधि ऋण	3,699	6,612	15,930	-1,985	7,558	-49	6,749
IV.	बैंकिंग पूंजी (निवल)	1,373	1,913	11,759	-3,246	2,084	1,045	834
	जिसमें							
	अनिवासी-जमा राशियां (निवल)	2,789	4,321	179	4,290	2,924	2,865	2,163
V.	विदेशी निवेश (निवल)	15,528	14,753	43,326	5,785	51,167	30,275	29,137
	जिसमें							
क.	एफडीआई (निवल)	3,034	7,693	15,893	19,816	18,771	12,330	5,340
ख.	पोर्टफोलियो (निवल)	12,494	7,060	27,433	-14,031	32,396	17,945	23,797
VI.	अन्य प्रवाह (निवल)*	660	4,047	10,847	-4,090	-13,113	-10,058	-9,026
III.	भूल-चूक	-516	968	1,316	1,067	-1,573	-92	-1,750
IV.	समग्र शेष**	15,052	36,606	92,164	-20,080	13,441	9,533	7,030
V.	प्रारक्षित निधियां (वृद्धि(-)/कमी()	(-) 15,052	(-) 36,606	(-) 92,164	20,080	(-) 13,441	(-) 9,533	(-) 7,030

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

आ.सं. : आंशिक रूप से संशोधित

प्रा. : प्राथमिक

* इसमें अन्य के साथ-साथ विलम्बित निर्यात प्राप्तियां तथा रुपया ऋण सेवा शामिल है।

** समग्र शेष में कुल चालू लेखा शेष, पूंजी लेखा शेष तथा भूल-चूक शामिल है।

से तुलना करने पर व्यापार तथा चालू लेखा घाटा और पूंजी प्रवाह उच्च था (सारणी 6.1)।

चालू खाता

पण्य व्यापार

6.19 2009-10 के दौरान भारत के चालू खाते की स्थिति में वैश्विक आर्थिक मंदी और विश्व व्यापार में मंदी का प्रभाव निरन्तर परिलक्षित हुआ है जो 2008-09 की दूसरी छमाही से जारी है। 2009-10 के दौरान बीओपी आधार पर भारत का 182.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का पण्य निर्यात ने वर्ष 2008-09 में 189.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 3.6 प्रतिशत की

गिरावट दर्ज की जो 2007-08 में 166.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 13.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार 300.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात भुगतान ने भी 2009-10 में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जबकि 2008-09 में यह 308.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था और यह 2007-08 में मौजूद 257.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात की तुलना में 19.8 प्रतिशत उच्च था। यद्यपि निर्यात में गिरावट आयात की तुलना में सापेक्ष रूप से उच्च थी, पण्य व्यापार घाटा निरपेक्ष रूप में मामूली घटकर 2009-10 के दौरान 118.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 8.6 प्रतिशत) हो गया जबकि 2008-09 में यह 119.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 9.8 प्रतिशत) था।

6.20 भारत के निर्यात का जिंसवार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कुल निर्यात में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा 2008-09 में 13.9 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 14.9 प्रतिशत होकर 100 आधार बिन्दुओं तक बढ़ गया। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान पेट्रोलियम, कच्चा तेल तथा उत्पादों (कोयला सहित) का हिस्सा 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गया। 2009-10 में प्राथमिक उत्पादों में 3.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर रही (जो 2008-09 में 1.7 प्रतिशत की तुलना में है) और पेट्रोलियम के संबंध में यह 2.3 प्रतिशत (जो 2008-09 में 3.0 प्रतिशत की तुलना में है)। ये 2009-10 में इन उत्पादों के हिस्से की वृद्धि हेतु जिम्मेदार हैं। तथापि, विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 2008-09 में 68.9 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 67.2 प्रतिशत हो गया, ऐसा 2008-09 में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 5.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के कारण हुआ। आयात मर्दानों में, पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक (पीओएल) का हिस्सा 2009-10 में घटकर 30.2 प्रतिशत हो गया जबकि 2008-09 में यह 31.3 प्रतिशत था, ऐसा 2009-10 में 7.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के कारण हुआ। आयात के अन्य मुख्य संघटक स्वर्ण तथा चांदी थे जिनका हिस्सा 2008-09 में 9.3 प्रतिशत से 2009-10 में 10.3 प्रतिशत होकर 100 आधार बिन्दुओं तक बढ़ गया, ऐसा 2008-09 में 22.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 35.5 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर के कारण हुआ। भारत के निर्यात निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण अगले अध्याय में किया जाएगा।

6.21 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर 2010) की पहली छमाही के दौरान भारत के चालू खाते घाटे की बढ़ती भारत तथा शेष विश्व के बीच विकास की असमानता के प्रभाव को दर्शाती है। भारत के निर्यात और आयात की वृद्धि गति जो 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान प्रारम्भ हुई, वह 2010-11 की पहली छमाही में भी जारी रही। बीओपी आधार पर, भारत के पण्य निर्यात ने 2010-11 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2010) तथा दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2010) में क्रमशः 43.6 प्रतिशत तथा 25.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 2009-10 की इसी तिमाहियों में हुई 31.8 प्रतिशत तथा 19.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में है। 2010-11 की पहली छमाही के दौरान, निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 25.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से तुलना करने पर 33.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी प्रकार, 2010-11 की पहली दो तिमाहियों के दौरान आयात में 34.2 प्रतिशत तथा 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो 2009-10 की इन्हीं तिमाहियों के दौरान 20.8 प्रतिशत तथा 21.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में है। आयात ने 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 28.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि 2009-10 की पहली छमाही के दौरान इसने 21.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। तेल, मोती तथा कम मूल्यवान पत्थरों के बढ़ते आयात ने बराबर बढ़ते आयात बिलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तेल आयात की बढ़ती मात्रा के साथ कच्चे तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि से 2010-11 की

पहली छमाही के दौरान तेल आयात बिलों में बढ़ती हुई। अप्रैल-सितम्बर 2010-11 के दौरान आयात की तुलना में उच्च निर्यात वृद्धि के बावजूद, व्यापार घाटे में निरपेक्ष रूप से 19.7 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 2010-11 की पहली छमाही में 66.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 55.9 बिलियन अमरीकी डालर था।

अदृश्य लेखे

6.22 अदृश्य बीओपी लेखा सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, अनिवासी परिसम्पत्तियों से सम्बद्ध आय तथा देयताएं, श्रम, सम्पत्ति, सीमा पार अन्तरण जिसमें मुख्यतः कामगार विप्रेषण शामिल है, से सम्बन्धित लेन-देन का संयुक्त प्रभाव परिलक्षित होता है। सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा कामगारों के विप्रेषणों के चालू प्राप्तियों के दो संघटक 2009-10 में सापेक्ष रूप से यथावत बने रहे जैसाकि 2008-09 में दिखाई दिया। यद्यपि वैश्विक आर्थिक मंदी थी और जो मुख्यतः निवल अदृश्य अधिशेष के लिए उत्तरदायी है।

6.23 2009-10 में 163.4 बिलियन अमरीकी डालर की अदृश्य प्राप्तियों ने 2008-09 में 167.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की (जो 2007-08 में 148.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2008-09 में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले है), ऐसा मुख्यतः कम निवेश आय सहित व्यापार वित्त तथा संचार सेवाओं जैसे विविध सेवाओं के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुआ। व्यापार सेवाओं के सभी संघटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों (जैसे व्यापार सम्बद्ध सेवाएं, कारोबार तथा प्रबन्ध परामर्शी सेवाएं, वास्तुकला, इन्जीनियरिंग तथा आय तकनीकी सेवाएं और विदेश स्थित कार्यालयों के रख-रखाव) ने 2009-10 के दौरान गिरावट प्रदर्शित की जो वैश्विक संकट का प्रभाव है। निवेश आय के अन्तर्गत प्राप्तियां 2009-10 में घटकर 12.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी जबकि पिछले वर्ष यह 13.5 बिलियन अमरीकी डालर थी, ऐसा विदेशों में व्यापार दरों की गिरावट के कारण था।

6.24 तथापि, 49.7 बिलियन अमरीकी डालर की सॉफ्टवेयर प्राप्तियों ने 2009-10 में 7.4 प्रतिशत की बढ़ती दर्ज की (जबकि पिछले वर्ष ये प्राप्तियां 14.9 प्रतिशत थी)। निजी अन्तरण प्राप्तियों जिनमें मुख्यतः विदेश स्थित भारतीय कामगारों के विप्रेषण शामिल हैं, में भी 2009-10 में 53.9 बिलियन अमरीकी डालर (सघड का 3.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में 46.9 बिलियन अमरीकी डालर (सघड का 3.8 प्रतिशत) था। निजी अन्तरण प्राप्तियों का हिस्सा 2009-10 में मौजूदा प्राप्तियों का 15.6 प्रतिशत था (2008-09 में 13.1 प्रतिशत)।

6.25 सॉफ्टवेयर सेवाओं, अन्तरण तथा निवेश आय को छोड़कर, सभी संघटकों के तहत भुगतानों में वृद्धि के कारण अदृश्य भुगतानों में 2009-10 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 2008-09 में 76.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2009-10

में 83.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। परिणामस्वरूप, भारत के निवल अदृश्य लेखे (भुगतान को घटाकर प्राप्तियां) 2009-10 में 80.0 बिलियन अमरीकी डालर (सघड का 5.8 प्रतिशत) था जिसने 2008-09 में 91.6 बिलियन अमरीकी डालर (सघड का 7.5 प्रतिशत) की तुलना में 12.7 की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। सेवा संघटकों के अन्तर्गत निवल प्राप्तियां (व्यापार, परिवहन, बीमा, जीएनआईई विविध) 33.8 प्रतिशत तक घटकर 2008-09 में 53.9 बिलियन अमरीकी डालर से 2009-10 में 35.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी। तथापि, सॉफ्टवेयर सेवाएं इसी अवधि के दौरान 43.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 48.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गयी और इनमें 10.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। अदृश्य लेखों के अन्य संघटक जिन्होंने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, वे अन्तरण अर्थात् विप्रेषण थे (निजी तथा सरकारी)। 2009-10 में निवल निजी अन्तरण 52.1 बिलियन अमरीकी डालर थे जो 2008-09 में 44.6 बिलियन अमरीकी डालर थे और ये 16.8 प्रतिशत उच्च थे।

6.26 भारत और शेष विश्व के बीच विकास असमानता का प्रभाव चालू राजकोषीय 2010-11 में भारत के अदृश्य लेखों में देखा गया जिस वजह से 2010-11 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर 2010) में निवल अदृश्य लेखों शेषों में मामूली वृद्धि हुई। यह मामूली वृद्धि मुख्यतः निवेश आय तथा निजी अन्तरण प्राप्तियों में गिरावट तथा सेवा भुगतानों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

6.27 निवल अदृश्य अधिशेष में 8.0 प्रतिशत गिरावट होकर 2010-11 की पहली छमाही के दौरान यह 39.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2009-10 की इसी अवधि के दौरान यह 42.5 बिलियन अमरीकी डालर था। ऐसा मुख्यतः सेवाओं की सभी मुख्य श्रेणियों तथा सकल निवेश आय प्राप्तियों के कारण उच्च अदृश्य भुगतानों (जिसमें पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 33.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई) की वजह से हुई और जो सेवाओं की सभी मुख्य श्रेणियों तथा सकल निवेश आय प्राप्तियों के कारण प्रभावित थी। मुख्यतः यात्रा परिवहन, कारोबार तथा वित्तीय सेवा के अन्तर्गत उच्च भुगतानों के कारण सेवा भुगतानों में 46.9 प्रतिशत (पिछले वर्ष 4.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले) तक वृद्धि हुई।

6.28 दूसरी ओर, काफी हद तक निवेश आय तथा निजी अन्तरणों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण गिरावट सेवा निर्यातों में बढ़ोतरी को प्रतिसंतुलित करती है। निवेश आय प्राप्तियों में 40.1 प्रतिशत की तीव्र गिरावट हुई (जो पिछले वर्ष की मामूली गिरावट की तुलना में है), ऐसा मुख्यतः विदेश में कम ब्याज दरों के बने रहने के कारण थी। 27.2 बिलियन अमरीकी डालर पर निजी अन्तरण प्राप्तियों ने भी 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की (जो पिछले वर्ष के 4.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में है)। तथापि, सेवा निर्यातों में इस अवधि दौरान काफी बदलाव दिखाई दिया जिसने 27.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (जो पिछले वर्ष के 16.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में है) और यह कारोबार, वित्त, सॉफ्टवेयर, यात्रा तथा परिवहन सेवाओं जैसे सेवाओं के सभी मुख्य घटकों की वजह से हुआ। इसको देखते हुए, अदृश्य

प्राप्तियों ने पिछले वर्ष के 8.9 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि, चूंकि अदृश्य भुगतान अदृश्य प्राप्तियों की तुलना में उच्च थी इसलिए अप्रैल-सितम्बर 2010 के दौरान निवल अदृश्य अधिशेष की मात्रा कम बनी रही। पिछले वर्ष भी इसी अवधि से तुलना करने पर अप्रैल-सितम्बर, 2010 के दौरान व्यापार घाटे का लगभग 58.3 प्रतिशत का वित्त पोषण निवल अदृश्य अधिशेष से किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 76.1 प्रतिशत के मुकाबले है।

6.29 वर्ष 2009-10 के दौरान सेवा प्राप्तियों में 2008-09 के 53.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से 33.8 प्रतिशत की कमी होने की वजह से माल एवं सेवा संतुलन अर्थात् सेवाओं सहित कारोबार संतुलन वर्ष 2009-10 में 2008-09 के 65.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 5.4 प्रतिशत) से बढ़कर 82.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 6.0 प्रतिशत) हो गया, जो 25.9 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के दौरान माल एवं सेवा संबंधी घाटा कारोबार घाटा बढ़ने की वजह से 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 36.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से 28.8 प्रतिशत बढ़कर 47.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि निवल सेवा प्राप्तियां कमोबेश समान स्तर पर बनी रहीं। (सारणी 6.1 तथा 6.2)

चालू खाता शेष

6.30 अदृश्य अधिशेष में गिरावट के परिणामस्वरूप, कम व्यापार घाटे के बावजूद वर्ष 2009-10 में मौजूदा खाता घाटा 2008-09 के 27.9 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 2.3 प्रतिशत) से 37.5 प्रतिशत बढ़कर 38.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 2.8 प्रतिशत) हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के उच्च व्यापार घाटे के साथ कम अदृश्य अधिशेष की वजह से चालू खाता घाटा अप्रैल-सितम्बर, 2009-10 के 13.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर दोगुने से भी अधिक 27.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (चित्र 6.1 और 6.2)

पूंजी खाता

6.31 भारत की विकास संभावनाओं के बारे में वैश्विक निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से वैश्विक सुधार के प्रति भारत के अपेक्षाकृत अधिक सुधार से वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजी प्रवाहों में पुनरुद्धार को बढ़ावा मिला। यह मुख्य परिवर्तन मुख्यतया विदेशी संस्थागत निवेशकों के तहत अधिक अंतर्प्रवाहों और अल्पावधिक कारोबारी ऋण के कारण हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान 345.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का सकल पूंजी अंतर्प्रवाह 2008-09 के 313.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 10.2 प्रतिशत अधिक था, जबकि 292.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का सकल पूंजी बहिर्प्रवाह 2008-09 के 306.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से 4.8 प्रतिशत कम रहा। परिणामस्वरूप, वर्ष 2009-10 के दौरान 53.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 3.8 प्रतिशत) निवल पूंजी प्रवाह वर्ष 2008-09 के 6.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (सघड का 0.5 प्रतिशत) के मुकाबले कहीं अधिक था।

सारणी 6.2 : वैदेशिक क्षेत्र के चयनित संकेतक								
क्रम सं.	मदें	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 आ.स.	2009-10 एच1 (अप्रैल-सित. 2009) आ.स.	2010-11 एच1 (अप्रैल-सित. 2010) प्रा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निर्यात वृद्धि-बीओपी (%)	23.4	22.6	28.9	13.7	-3.6	-25.7	33.8
2.	आयात वृद्धि-बीओपी (%)	32.1	21.4	35.1	19.8	-2.6	-21.1	28.2
3.	कारक भिन्न सेवाओं का विकास (जमा)	33.3	28.0	22.4	17.3	-9.6	-14.2	27.4
4.	कारक-भिन्न सेवाओं का विकास (ऋण)	24.0	28.5	16.2	1.1	15.3	-4.7	46.9
5.	निर्यात/आयात-बीओपी (प्रतिशत)	67.0	67.6	64.5	61.3	60.6	59.7	62.3
6.	निर्यात/आयात वस्तुएं और सेवाएं (प्रतिशत)	85.0	86.2	83.0	92.7	90.0	77.5	77.8
7.	एफईआर का आयात कवर (महीनों की संख्या)	11.6	12.5	14.4	9.8	11.1	-	-
8.	बाह्य सहायता (निवल/टीसी) (%)	6.7	3.9	2.0	36.1	5.4	4.5	8.2
9.	ईसीबी निवल/टीसी (%)	9.8	35.6	21.2	116.2	5.3	3.2	16.3
10.	एनआर निक्षेप/टीसी (%)	11.0	9.6	0.2	63.4	5.5	12.5	5.9
जीडीपी एमपी के प्रतिशत के अनुसार								
11.	निर्यात	12.6	13.6	13.4	15.4	13.2	13.9	14.5
12.	आयात	18.8	20.1	20.8	25.2	21.7	23.4	23.2
13.	व्यापार सन्तुलन	-6.2	-6.5	-7.4	-9.8	-8.6	-9.4	-8.8
14.	अदृश्य अधिशेष	5.0	5.5	6.1	7.5	5.8	7.2	5.1
15.	वस्तु और सेवा शेष	-3.4	-3.4	-4.2	-5.4	-6.0	-6.2	-6.2
16.	चालू लेखा शेष	-1.2	-1.0	-1.3	-2.3	-2.8	-2.2	-3.7
17.	ईसीबी	0.3	1.7	1.8	0.7	0.2	1.0	0.1
18.	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	0.4	0.8	1.3	1.6	1.4	0.9	1.7
19.	पोर्टफोलियो निवेश (निवल)	1.5	0.7	2.2	-1.2	2.4	3.8	2.5
20.	जोड़ पूंजी लेखा (निवल)	3.0	4.7	8.6	0.5	3.8	3.9	4.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

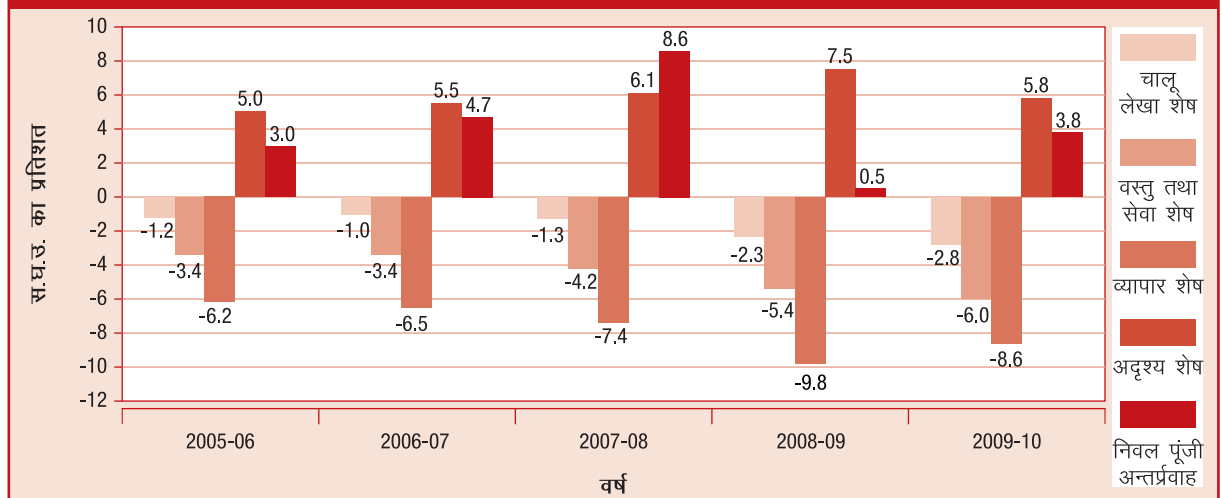
आ.स. : आंशिक रूप से संशोधित

प्रा. : प्राथमिक

टीसी: कुल पूंजीगत प्रवाह (निवल)
ईसीबी: बाह्य वाणिज्यिक उधार

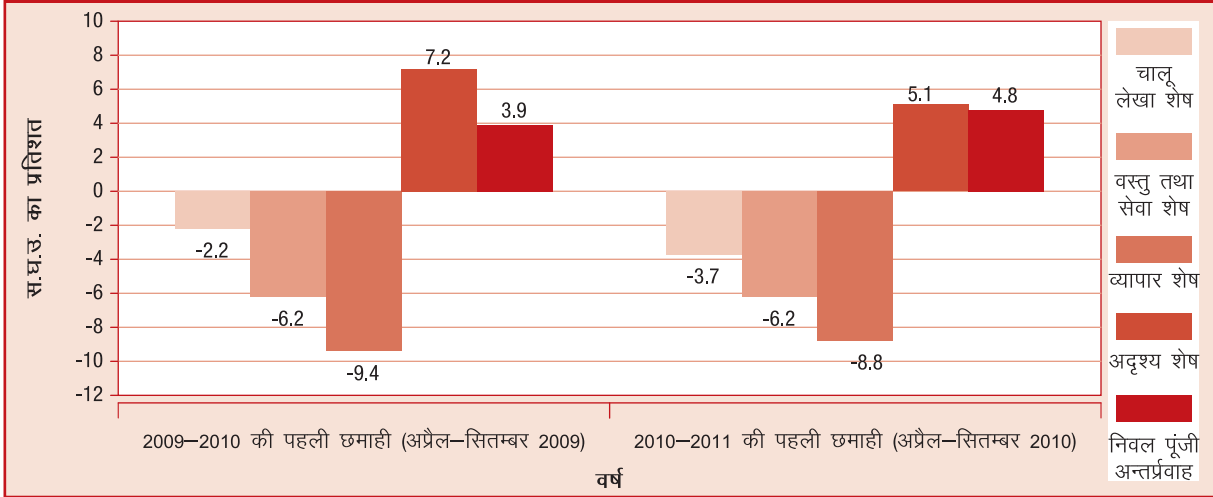
एफईआर: विदेशी मुद्रा भंडार
जीडीपी एमपी: चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में।

चित्र 6.1 2005-06 से 2009-10 के दौरान सघउ के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा शेष, वस्तु तथा सेवा, व्यापार शेष, अदृश्य शेष तथा निवल पूंजी अन्तर्प्रवाह



चित्र 6.2

2009-10 तथा 2010-11 की पहली छमाही के दौरान सघट के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा शेष, वस्तु तथा सेवा, व्यापार शेष, अदृश्य शेष तथा निवल पूंजी अन्तर्प्रवाह



6.32 वर्ष 2009-10 के दौरान आवक और जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों में वर्ष 2008-09 की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। इसी प्रकार, वर्ष 2009-10 में जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2008-09 के 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से 19.6 प्रतिशत गिरकर 14.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। परिणामस्वरूप, 2008-09 के 19.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2009-10 में 18.8 बिलियन अमरीकी डॉलर होकर (बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश घटाकर आन्तरिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) मामूली रूप से कम रहा और यह निवेश मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र में तथा इसके पश्चात् भवन-निर्माण, वित्तीय सेवाएं और स्थावर संपदा क्षेत्रों में आया।

6.33 वर्ष 2009-10 में पोर्टफोलियो निवेश के क्षेत्र में 2008-09 के 14.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल बहिर्प्रवाह के मुकाबले 32.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल अंतर्प्रवाह देखा गया। आकर्षक घरेलू बाजार दशाओं ने वर्ष 2009-10 में 29.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल विदेशी संस्थागत निवेश का मार्ग प्रशस्त किया (वर्ष 2008-09 के 15.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल बहिर्प्रवाह के मुकाबले)। वर्ष 2009-10 में एडीआर/जीडीआर का स्तर 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर पर 2008-09 के उसी स्तर के बराबर रहा। वर्धित वापसी अदायगियों के कारण निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार गिरकर 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (वर्ष 2008-09 में 7.9 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गए।

6.34 भारत को प्राप्त होने वाले निवल अल्पावधिक कारोबारी ऋणों में एक वर्ष पहले के 2.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवल बहिर्प्रवाहों में बढ़ोत्तरी हुई जो महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 7.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। यह घरेलू आयातकों में अंतरराष्ट्रीय विश्वास का प्रदर्शन करता है और वर्ष 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान अनिवासी जमा राशियों के तहत निवल अंतर्प्रवाह दर्ज करने के पश्चात् अंतिम तिमाही में बहिर्प्रवाह देखा गया। अनिवासी जमा राशियों का वर्ष 2009-10 के दौरान 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का समग्र निवल जमा अंतर्प्रवाह 2008-09 के 4.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में कम रहा।

6.35 वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के दौरान मुख्यतया विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्प्रवाहों, अल्पावधिक कारोबारी ऋणों और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के कारण निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई। एक वर्ष पूर्व के 15.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2010 के दौरान 22.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्प्रवाह अधिक रहा जो भारतीय स्टॉक बाजार से प्राप्त होने वाले आकर्षक प्रतिलाभ को दर्शाता है। तीव्र घरेलू मांग और भारत और विदेशों में उच्च ब्याज दर विभेदक जारी रहने की पृष्ठभूमि में अल्पावधिक कारोबारी ऋणों और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्प्रवाह में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई। तदनुसार, अप्रैल-सितम्बर, 2010 के दौरान अल्पावधिक कारोबारी ऋण 2009-10 की इसी अवधि की मामूली बहिर्प्रवाह के मुकाबले बढ़कर 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधार के तहत निवल अंतर्प्रवाह एक वर्ष पूर्व के 0.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंतर्प्रवाह के मुकाबले बढ़कर 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इन अन्तर्प्रवाहों में हुई भारी वृद्धि को निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संतुलक द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो आन्तरिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट के कारण 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि 2009-10 की उसी अवधि के दौरान यह 12.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। आन्तरिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 19.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 36.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज कर 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 12.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (आवक-जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) में हुई कमी से इन अंतर्प्रवाहों में हुई अधिक बढ़ोत्तरी वर्ष 2010-11 की पहली छमाही के दौरान, 2009-10 की इसी अवधि के दौरान हुए 12.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मंदी आई और यह 5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, इसकी वजह आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट रही। वर्ष 2009-10 की

पहली छमाही में आवक एफडीआई 2009-10 की पहली छमाही के 19.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से 36.4 प्रतिशत गिरकर 2010-11 की पहली छमाही में 12.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई। तथापि, वर्ष 2010-11 के पहली छमाही में जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विगत वर्ष के पहली छमाही के 7.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर कमोबेश समान स्तर पर बना रहा। 2009-10 की पहली छमाही के निवल पूंजी प्रवाह में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा 53.7 प्रतिशत से घटकर मौजूदा राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही में 14.6 प्रतिशत हो गया। मौजूदा लेखा घाटा की अपेक्षा पूंजी लेखा अधिशेष उच्च होने से, समग्र शेष 7.0 बिलियन अमरीकी डॉलर पर अधिशेष रूप में था, जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2010-11 की पहली छमाही के दौरान समकक्ष राशि की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की निवल अनुवृद्धि हुई।

6.36 पूंजी अंतर्प्रवाहों संबंधी नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल-नवम्बर 2010 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्प्रवाह 19.0 बिलियन अमरीकी डॉलर पर विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान के स्तर के लगभग बराबर रहा। तथापि, अप्रैल-नवम्बर 2010 में विदेशी संस्थागत निवेश सहित पोर्टफोलियो निवेश संबंधी अंतर्प्रवाह एक वर्ष पूर्व के 22.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से तेजी से बढ़कर 32.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। विदेशी संस्थागत निवेश में हुई बढ़ोतरी का श्रेय अपेक्षाकृत सुदृढ़ आर्थिक मूल भूत तत्वों और कई उन्नत देशों द्वारा अपनाई गई आसान मौद्रिक नीतियों के कारण वर्धित अंतरराष्ट्रीय नकदीकरण को दिया जा सकता है।

6.37 मुख्यतया पोर्टफोलियो निवेशों के तहत उच्च अंतर्प्रवाह और अल्पावधिक कारोबारी ऋणों के तहत उच्च अंतर्प्रवाह कम निवल अदृश्य अधिशेष और अधिक निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों के कारण था जो वर्ष 2009-10 के दौरान भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं और चालू राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही में उच्च चालू खाता घाटा की वजह से था, तब इससे विदेशी मुद्रा भंडारों की भुगतान संतुलन के आधार पर निवल अनुवृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

6.38 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां भुगतान संतुलन (बीओपी) के एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं और अर्थव्यवस्था की बाह्य स्थिति के विश्लेषण में एक अनिवार्य तत्व होते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का स्तर मुख्यतः विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का परिणाम है जिससे विनिमय दर की अस्थिरता और अमरीकी डॉलर के विश्व की अन्य मुख्य मुद्रा के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति के कारण मूल्य परिवर्तन पर नियंत्रण हो सके। विदेशी मुद्रा भंडारों में संचयन अधिक तब होता है जब भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार, सहायता प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), और अंतरराष्ट्रीय

विकास संघ (आईडीए) जैसी संस्थाओं से प्राप्त निधिपोषण में हस्तक्षेप के जरिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रवाह का उपयोग करता है। अमरीकी डॉलर और यूरो दोनों मध्यवर्ती मुद्राएं हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, आस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसी प्रमुख मुद्राओं में रखी जाती हैं। भंडारों का मूल्य वर्ग तथा इन्हें अमरीकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है, जो इस प्रयोजन हेतु अंतरराष्ट्रीय निर्देशांक है।

6.39 सुरक्षा और नकदीकरण के दो उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि प्रबंधन के निर्देशक सिद्धांत है जिसके फ्रेमवर्क के भीतर अधिकतम प्रतिलाभ की कार्ययोजना निहित है। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् स्व-बीमा तंत्र के रूप में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के निर्माण की लागतों पर बहस छिड़ी है। यह स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है कि विदेशी मुद्रा भंडारों ने भारत को संकट के अत्यंत बुरे प्रभाव से बचाने में मदद की है। बहस के एक मुद्दे के अनुसार, पूर्व-व्यवस्थित ऋण श्रृंखला का बहुपक्षीय विकल्प जिसे आसानी से और शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, महंगा बीमा विकल्प हो सकता है। तथापि, ऐसा बहुपक्षीय विकल्प आवश्यक होता है परन्तु यह पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि विदेशी निवेशक निवेश संबंधी निर्णयों में अक्सर विदेशी मुद्रा भंडारों के आकार को मुख्य जानकारी के रूप में देखते हैं।

6.40 किसी देश में स्व-बीमा के भंडारों के स्तर और प्रमात्रा के मूल्यांकन में उन देशों के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण है जहां भंडार चालू खाता अधिशेषों का परिणाम होते हैं और चालू खाता घाटों वाली अर्थव्यवस्थाओं, जिनके भंडार उनकी अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता से अधिक पूंजी अंतर्प्रवाहों का परिणाम होते हैं। भारत उत्तरवर्ती श्रेणी में आता है जिसमें भंडारों के तहत मुख्यतया पोर्टफोलियो (एफआईआई) निवेश, जिसका स्वरूप अचानक विराम और विपर्यय के प्रति असुरक्षित होता है।

भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

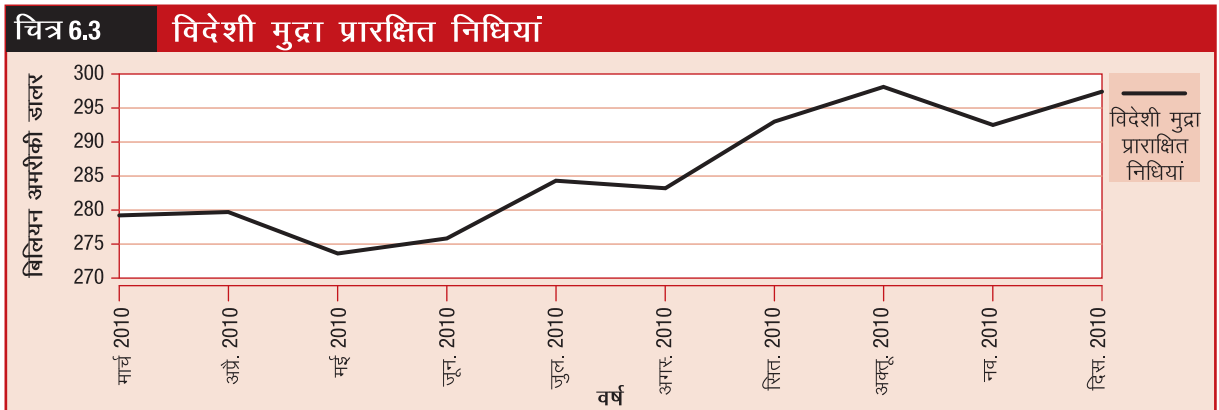
6.41 भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां मार्च, 1991 के अंत में 5.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के निम्न स्तर से आरंभ होकर धीरे-धीरे बढ़कर मार्च, 1995 के अंत में 25.2 बिलियन अमरीकी डॉलर, मार्च, 2000 के अंत तक 38.0 बिलियन अमरीकी डॉलर, मार्च, 2004 के अंत तक 113.0 बिलियन अमरीकी डॉलर और मार्च, 2007 के अंत तक 199.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी। मार्च, 2009 के अंत में 252.0 बिलियन अमरीकी डॉलर तक गिरने से पहले ये प्रारक्षित निधियां मई, 2008 के अंत में 314.6 बिलियन डॉलर के शीर्ष पर पहुंच चुकी थीं। अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2008-09 में प्रारक्षित निधियों में हुई गिरावट वैश्विक संकट और अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती थी। वर्ष 2009-10 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर पुनः मार्च, 2010 के अंत में बढ़कर 279.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण मूल्य वृद्धि है क्योंकि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था। वर्ष 1950-51 से 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का रूप और अमरीकी डॉलर में संघटकवार ब्यौरा परिशिष्ट 6.1 (क) और 6.1 (ख) में दिया गया है।

सारणी 6.3 : भुगतान संतुलन आधार पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत और मूल्यन प्रभाव (बिलियन अमरीकी डॉलर)					
क्र. सं.	मद	अप्रैल-सितम्बर			
		2008-09	2009-10	2009-10 ^{आ.स.}	2010-11 ^{प्रा.}
1	2	3	4	5	6
I.	चालू खाता शेष	(-) 27.9	(-) 38.4	(-) 13.3	(-) 27.9
II.	पूँजी लेखा (निवल) (क से छ)	7.9	51.8	22.7	33.1
	(क) विदेशी निवेश (i+ii)	5.8	51.2	30.3	29.1
	(i) एफडीआई	19.8	18.8	12.3	5.3
	(ii) पोर्टफोलियो निवेश जिसका	(-) 14.0	32.4	17.9	23.8
	एफआईआई	(-) 15.0	29.0	15.3	22.3
	एडीआर/जीडीआर	1.2	3.3	2.7	1.6
	(ख) विदेशी वाणिज्यिक उधार	7.9	2.8	0.7	6.0
	(ग) बैंकिंग पूँजी जिसका : अप्रवासी जमाराशियां	(-) 3.2	2.1	1.0	0.8
	(घ) अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट	4.3	2.9	2.9	2.2
	(ङ) विदेशी सहायता	(-) 2.0	7.6	-0.1	6.7
	(च) पूँजी लेखा में अन्य मदें*	2.4	2.9	1.0	3.0
	(छ) भूल-चूक	(-) 4.1	(-) 13.1	(-) 10.2	(-) 10.7
	(ज) समग्र शेष (i+ii)	1.1	(-) 1.6	(-) 0.1	(-) 1.8
III.	भुगतान संतुलन आधार पर आरक्षित परिवर्तन (वृद्धि/कमी+)	(-) 20.1	13.4	(-) 9.5	(-) 7.0
IV.	मूल्यन परिवर्तन जोड़ आरक्षित परिवर्तन (III+IV) (आरक्षित निधियों में वृद्धि (+)/आरक्षित निधियों के कमी (-)	(-) 37.6	13.6	19.8	6.8
		(-) 57.7	27.0	29.3	13.8

स्रोत: आरबीआई आ.सं. : आंशिक रूप से संशोधित प्रा. : प्राथमिक टिप्पणी*: 'पूँजी लेखा में अन्य मदों' में एसडीआर आवंटन, निर्यातों में अग्रता और अन्तराल, विदेशों में स्थित निधियों, एफडीआई के तहत शेयरों के बकाया निर्गम प्राप्त अग्रिम और पूँजी प्राप्तियों का लेनदेन शामिल है, जो कहीं अन्यत्र शामिल नहीं है। भुगतान संतुलन की संकलन प्रक्रिया के अनुसार, भंडारों में वृद्धि (-) चिन्ह और कमी (+) चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। अन्य मदों में (+) का चिन्ह वृद्धि और (-) का चिन्ह कमी को दर्शाते हैं। यदि कोई अन्तर हो तो वह पूर्णांक के कारण है।

6.42 वर्ष 2009-10 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों में हुई कुल 27.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी में से वर्ष 2009-10 के दौरान हुई 13.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि मूल्य वृद्धि और 13.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का शेष भुगतान संतुलन के आधार पर प्राप्त हुआ (सारणी 6.3)। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों में हुई बढ़ोतरी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

(आईएमएफ) द्वारा भारत को दि. 28 अगस्त 2009 को सामान्य आवंटनों के तहत 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,821 मिलियन डॉलर के समतुल्य) और दि. 9 सितम्बर 2009 को विशेष आवंटनों के तहत 214.6 मिलियन एसडीआर (340 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) के दो क्रमिक किशतों में किए गए एसडीआर आवंटन शामिल हैं। नवम्बर 2009 में आईएमएफ के



सारणी 6.4 : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में परिवर्तनों का सारांश (बिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र. सं.	वर्ष	वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां	पिछली अवधि की तुलना में प्रारक्षित निधियों में वृद्धि/कमी	भुगतान संतुलन के आधार पर प्रारक्षित निधियों में वृद्धि/कमी	मूल्यन प्रभाव के कारण प्रारक्षित निधियों में वृद्धि/कमी
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	151.6	+ 10.1	+ 15.0 (148.5)	- 4.9 (- 48.5)
2	2006-07	199.1	+ 47.5	+ 36.5 (76.8)	+ 11.0 (23.2)
3	2007-08	309.7	+ 110.6	+ 92.2 (83.4)	+ 18.4 (16.6)
4	2008-09	252.0	- 57.7	-20.1 (34.8)	- 37.6 (65.2)
5	2009-10	279.1	+ 27.0	+ 13.4 (49.6)	+ 13.6 (50.4)
6	2010-11 (सितम्बर 2010 तक)	292.9	+ 13.8	+ 7.0 (50.7)	+ 6.8 (49.3)

स्रोत : आरबीआई

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल परिवर्तन के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

सीमित सोना बिक्री कार्यक्रम के तहत इसके विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन अभियान के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ से 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत पर 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद भी शामिल है।

6.43 चालू राजकोषीय वर्ष 2010-11 में माह-दर-माह आधार पर विदेशी मुद्रा भंडारों ने बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है। मुद्रा भंडार मार्च 2010 के अंत के 279.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 18.2 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर दिसम्बर, 2010 के अंत तक 297.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (चित्र 6.3)। भंडार का यह स्तर लगभग 10 माह की आयात कवर करता है।

6.44 वर्ष 2005-06 से विदेशी मुद्रा भंडार में हुए परिवर्तनों का सारांश और भुगतान संतुलन आधार पर वृद्धि/कमी तथा मूल्यन प्रभाव का ब्यौरा सारणी 6.4 में प्रस्तुत है।

6.45 भारत में एफसीए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक है। एफसीए मार्च 2010 के अंत के 254.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से 13.1 बिलियन (5.1 प्रतिशत) बढ़कर दिसम्बर 2010 के अंत में 267.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। यह बढ़ोतरी मुख्यतया मूल्यन वृद्धि, सहायता प्राप्तियां और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलरों की खरीद के कारण हुई।

6.46 क्रय शक्ति, जोखिम को न्यूनतम करना और प्रतिलाभों में अस्थिरता और नकदीकरण बनाए रखने की दृष्टि से प्रारक्षित निधियों के दीर्घकालिक मूल्य के परिरक्षण के सिद्धांतों की तर्ज पर, भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख परिवर्तनीय मुद्रा लिखतों में एफसीए धारित करता है। इसमें अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और शीर्ष क्रम के विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां और सम्प्रभु देशों और अधिराष्ट्र संस्थाओं

के ऋण को दर्शाने वाली प्रतिभूतियां जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता 10 वर्ष से अधिक न हो, शामिल हैं और जिनका उद्देश्य पूंजी परिरक्षण और नकदी के संबंध में ठोस पक्ष प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के बहु-मुद्रा बहु-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो पर अवमूल्यन को घटाकर प्रतिलाभ की वार्षिकीकृत

सारणी 6.5 : कुछ मुख्य देशों की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

क्रम	देश	2009 के दौरान विदेशी प्रारक्षित निधियां (बिलियन अमरीकी डॉलर)
1	2	3
1.	चीन (जून 2010)	2,454.3
2.	जापान (दिसम्बर 2010)	1,118.8
3.	रूस (दिसम्बर 2010)	479.4
4.	भारत (दिसम्बर 2010)	297.3
5.	कोरिया (अक्टूबर 2010)	293.5
6.	ब्राजील (नवम्बर 2010)	285.5
7.	चीन पीआर हांग कांग (दिसम्बर 2010)	268.8
8.	सिंगापुर (दिसम्बर 2010)	225.8
9.	जर्मनी (दिसम्बर 2010)	216.6
10.	फ्रांस (दिसम्बर 2010)	188.3
11.	इटली (अक्टूबर 2010)	157.4

स्रोत : चीन को छोड़कर आईएमएफ

चीन के संबंध में : www.safe.gov.cn.

सारणी 6.6 : विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की अन्तरराष्ट्रीय तुलना (बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा वस्तु और सेवाओं के आयातों के सम्बंध में प्रारक्षित निधियों का अनुपात

क्रम सं.	देश/देश समूह	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (अनुमानित)	2011 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I देश								
1	रूस	176.5 (107.4)	296.2 (141.7)	467.6 (165.5)	412.7 (112.3)	417.8 (164.8)	468.7 (152.8)	508.1 (143.8)
2	चीन	822.5 (115.5)	1069.5 (125.4)	1531.3 (148.0)	1950.3 (158.2)	2348.8 (211.0)	2693.4 (169.6)	3025.6 (157.8)
3	भारत	132.5 (72.8)	171.3 (75.5)	267.6 (95.1)	248.0 (71.5)	266.2 (81.6)	281.6 (76.2)	295.9 (69.7)
4	ब्राजील	53.3 (54.4)	85.2 (70.7)	179.5 (113.8)	192.9 (87.6)	237.4 (135.9)	274.9 (117.9)	292.7 (110.0)
5	मेक्सिको	74.1 (30.5)	76.3 (27.4)	87.1 (28.5)	95.1 (28.5)	99.6 (38.7)	119.6 (35.9)	129.6 (36.5)
II समूह देश								
1	विकासशील एशिया (चीन ओर भारत को छोड़कर)	201.1 (38.6)	248.5 (42.5)	330.0 (49.1)	335.5 (41.8)	393.0 (60.2)	459.4 (58.2)	508.2 (58.4)

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटा बेस, अक्टूबर 2010

टिप्पणी : प्रारक्षित निधियाँ एसडीआर 35 प्रति औंस पर मूल्यित सोने की अधिकारिक धारिता पर आधारित है। इस परम्परा के परिणामस्वरूप वे देश जिनके पास पर्याप्त स्वर्ण धारिता है, वहाँ भंडारों को न्यून अनुमानन चिह्नित किया गया है।
लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रारक्षित निधियों और वस्तु तथा सेवा आयात के अनुपात को दर्शाते हैं।

दर वर्ष 2008-09 के 4.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 2.1 प्रतिशत हो गयी।

6.47 विदेशी मुद्रा भंडार का देशवार ब्यौरा यह दर्शाता है कि भारत के पास विश्व में चीन, जापान और रूस के बाद सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है (सारणी 6.5)।

6.48 भारत सहित चुनिंदा देशीय समूह और देशों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार और माल एवं सेवाओं के आयात के अनुपात द्वारा यथा मापित विदेशी मुद्रा भंडार और आयात कवर का तुलनात्मक अध्ययन सारणी 6.6 में दिया गया है। देशीय समूहों के मध्य, वर्ष 2005-09 के दौरान “विकासशील एशिया और “मध्य-पूर्व” संचित भंडार में माल एवं सेवाओं के आयात और भंडार के अनुपात में सुधार किया है।

विनिमय दरें

6.49 विनिमय दर नीति का संचालन लचीलेपन के साथ विनिमय दरों की सतर्क मॉनिटरिंग और प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों द्वारा किया जाता है और निहित मांग और आपूर्ति की दशाओं की अनुमति दी जाती है जिससे कि किसी अवधि में इसके संचालनों का निर्धारण किया जा सके। इस प्रमुख उद्देश्य के अधीन विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से

अतिरिक्त अस्थिरता को कम करने का लक्ष्य, अस्थिर करने वाले अव्यवहारिक कार्यकलापों की रोकथाम, प्रारक्षित निधियों का पर्याप्त स्तर बनाए रखना और एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करने से निर्देशित होता है।

6.50 वर्ष 2009-10 के दौरान, पूंजी अंतर्प्रवाहों की पृष्ठभूमि में और सकारात्मक विकास संभावना से रूप में सामान्यतः अमरीकी डॉलर के मुकाबले मूल्य वृद्धि हुई, हालांकि आवर्तक अवमूल्यन दबाव बने रहे। बाजार में असमान आपूर्ति स्थिति से वायदा प्रीमियम में भी कमी आई।

6.51 बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर रूप का मूल्य जहां 31 मार्च, 2009 को 50.95 प्रति अमरीकी डॉलर था, उसने 2009-10 की दूसरी छमाही में सामान्यतः अधिमूल्यन प्रवृत्ति के साथ दोतरफा संचलन दर्शाया। वर्ष 2009-10 में रूप का अधिमूल्यन विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्प्रवाह के कारण हुआ और इसमें तीव्र बृहत् आर्थिक निष्पादन और बेहतर प्रतिलाभ की वजह से तेजी आई। निर्यात में वृद्धि, सतत् पूंजी अंतर्प्रवाह और कुछ प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर के कमजोर होने से रूप पर अधिमूल्यन दबाव पड़ा और रुपया अमरीकी डॉलर विनिमय दर मार्च, 2010 के अंत तक 45.14 प्रति अमरीकी डॉलर हो गया।

सारणी 6.7 : वर्ष 2010-11 के दौरान प्रति विदेशी मुद्रा रुपए की विनिमय दरें और विनिमय बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की बिक्री/खरीद

माह	मासिक औसत विनिमय दरें (रुपया प्रति विदेशी मुद्रा)*				भारतीय रिजर्व बैंक की निवल बिक्री (-)/खरीद (+) (अमरीकी डॉलर मिलियन में)
	अमरीकी डॉलर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन**	
1	2	3	4	5	6
2009-10	47.42	75.89	67.08	51.10	(-) 2,505
मार्च 2010	(-3.0)	(3.2)	(-3.0)	(-9.6)	
2010-11	45.50	68.44	61.77	50.18	
अप्रैल 2010	44.50	68.24	59.66	47.63	-
	(2.2)	(0.3)	(3.5)	(5.4)	
मई 2010	45.81	67.23	57.67	49.69	-
	(-2.9)	(1.5)	(3.5)	(-4.1)	
जून 2010	46.57	68.70	56.90	51.22	110.0
	(-1.6)	(-2.1)	(1.4)	(-3.0)	
जुलाई 2010	46.84	71.52	59.76	53.43	-
	(-0.6)	(-3.9)	(-4.8)	(-4.1)	
अगस्त 2010	46.57	72.97	60.14	54.53	-
	(0.6)	(-2.0)	(-0.6)	(-2.0)	
सितम्बर 2010	46.06	71.68	60.08	54.50	260.0
	(1.1)	(1.8)	(0.1)	(0.1)	
अक्टूबर 2010	44.41	70.39	61.72	54.28	450.0
	(3.7)	(1.8)	(-2.7)	(0.4)	
नवम्बर 2010	45.02	71.85	61.50	54.57	870.0
	(-1.4)	(-2.0)	(0.4)	(-0.5)	
दिसम्बर 2010	45.16	70.46	59.69	54.24	-
	(-0.3)	(2.0)	(3.0)	(0.6)	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

*एफईडीएआई निर्देशात्मक दर; **प्रति 100 येन।

लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत माह/वर्ष की तुलना में अधिमूल्यन (+) और हास (-) दर्शाते हैं।

6.52 31 मार्च 2010 और 31 दिसम्बर 2010 के बीच रुपए में प्रति अमरीकी डॉलर 0.7 प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ और यह 44.81 रुपए प्रति डॉलर हो गया। इसी अवधि में रुपए में पाउंड (स्टर्लिंग) के मुकाबले 2.5 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले 12.1 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ, जबकि यूरो के मुकाबले इसमें 1.2 प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ।

6.53 राजकोषीय वर्ष 2009-10 में रुपए का पाउंड स्टर्लिंग को छोड़कर सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन वार्षिक औसत आधार पर हुआ। वर्ष 2008-09 में प्रति अमरीकी डॉलर रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर 45.99 और 2009-10 में इसमें 3.1 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ और यह 47.42 रुपए हो गई। इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 में रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर प्रति यूरो 65.06 और प्रति 100 जापानी येन 46.20 थी और 2009-10 के दौरान यह क्रमशः 3.0 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत गिरकर 67.08 और 51.10 हो गई थी। तथापि, प्रति पाउंड स्टर्लिंग रुपए की वार्षिक औसत विनिमय दर में 3.2

प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ और यह 2008-09 के 78.32 प्रति पाउंड स्टर्लिंग से 2009-10 में 75.89 रुपए हो गया।

6.54 रुपए की मासिक औसत विनिमय दर सामान्यतः रेंजबद्ध रही है और अप्रैल-दिसम्बर 2010 के दौरान 44-47 प्रति अमरीकी डॉलर के बीच रही है। दिसम्बर 2010 में रुपए की विनिमय दर (भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ [एफईडीएआई] द्वारा किए गए क्रय और विक्रय की मासिक औसत) अप्रैल 2010 के 44.50 प्रति अमरीकी डॉलर से अमरीकी डॉलर के मुकाबले 1.5 प्रतिशत गिरकर 45.16 प्रति अमरीकी डॉलर हो गई थी। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान रुपए में पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 3.2 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले 12.2 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ।

6.55 वर्ष 2010-11 के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले रुपए की माहवार विनिमय दर और विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री का ब्यौरा सारणी 6.7 में दिया गया है।

सारणी 6.8 : वर्ष 2010-11 के दौरान रुपए का संचलन और नीर तथा रीर सूचकांक

माह/वर्ष	रुपया प्रति डॉलर	विगत माह की तुलना में प्रति डॉलर रुपए में अधिमूल्यन (+) हास (-)	नीर*	रीर*	नीर में विगत माह की तुलना में अधिमूल्यन (+) / हास (-)	रीर में विगत माह की तुलना में अधिमूल्यन (+) / हास (-)
1	2	3	4	5	6	7
मार्च 2008	40.36		70.94	110.98		
मार्च 2009	51.23	-21.2	60.45	95.44	- 14.8	- 14.0
मार्च 2010	45.50	12.6	66.59	114.49	10.2	20.0
2010-11						
अप्रैल 2010 (अ)	44.50	2.2	68.40	118.92	2.7	3.9
मई 2010 (अ)	45.81	- 2.9	68.07	120.00	- 0.5	0.9
जून 2010 (अ)	46.57	- 1.6	67.55	118.78	- 0.8	- 1.0
जुलाई 2010 (अ)	46.84	- 0.6	65.70	116.18	- 2.7	- 2.2
अगस्त 2010 (अ)	46.57	0.6	65.66	116.53	- 0.1	0.3
सितम्बर 2010 (अ)	46.06	1.1	66.00	117.54	0.5	-0.9
अक्तूबर 2010 (अ)	44.41	3.7	66.68	118.25	1.0	0.6
नवम्बर 2010 (अ)	45.02	- 1.4	66.10	117.48	- 0.9	- 0.7
दिसम्बर 2010 (अ)	45.16	- 0.3	66.80	118.71	1.1	1.0

स्रोत : भार.रि.बैं.

* 6 मुद्रा व्यापार आधारित भार आधार : 1993-94 (अप्रैल-मार्च) =100 अ : अन्तिम

6.56 परिशिष्ट 6.5 1980-81 से वर्षवार और 2010-11 के दौरान माहवार चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर दर्शाता है।

नीर और रीर

6.57 अंकित प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) सूचकांकों को एक समयावधिक देश की विदेशी प्रतिस्पर्धा के संकेतकों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नीर (एनईईआर) विदेशी मुद्राओं के सन्दर्भ में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय अंकित विनिमय दरों की भारत औसत है, जबकि रीर (आरईईआर) अंकित विनिमय दरें जो घरेलू और विदेशी मूल्य विभेदकों को समायोजित करती है, भारत औसत के रूप में परिभाषित हैं। भारत और इसके मुख्य व्यापारिक भागीदारों के बीच अन्तरराष्ट्रीय विनिमय दर और मुद्रास्फीति विभेदकों में रीर की हलचल होती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक छह मुद्रा (अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, चीनी रेनमिनबी और हांगकांग डॉलर) और 36 मुद्रा नीर और रीर सूचकांकों को तैयार कर रही है।

6.58 मार्च 2009 और मार्च 2010 के बीच बिन्दू दर-बिन्दू आधार पर छह मुद्रा व्यापार आधारित रीर (आधार: 1993-94=100) में 20.0 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। वर्तमान

राजकोष में मार्च 2010 और दिसम्बर 2010 के बीच इसकी 3.7 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। मुद्रास्फिति सूचकांक को शामिल कर मुख्य व्यापार भागीदारों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में कमी इसका संकेत है। तथापि, भारत का विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा अमरीकी डॉलरों में लिखा और निर्धारित किया जाता है। रीर एक सीमा तक रुपए की प्रतिस्पर्धा का कम प्रभावी संकेतक है।

6.59 छह मुद्रा व्यापार आधारित नीर (आधार: 1993-94=100) की मूल्यवृद्धि मार्च 2009 और मार्च 2010 के बीच 10.2 प्रतिशत और मार्च 2010 और दिसम्बर 2010 के बीच 0.3 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, रुपए की मासिक औसत विनिमय दर की मूल्य वृद्धि मार्च 2009 और मार्च 2010 के बीच 12.6 प्रतिशत और अमरीकी डॉलर की तुलना में 0.8 प्रतिशत होकर यह मार्च 2010 में 45.50 प्रति अमरीकी डॉलर से दिसम्बर 2010 में 45.16 प्रति अमरीकी डॉलर हो गया।

अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डॉलर विनिमय दर

6.60 2009-10 (मार्च 2009-मार्च 2010) के दौरान अमरीकी डॉलर का मुख्य मुद्राओं की तुलना में मूल्यहास हुआ। इसमें पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में 4.9 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 1.7 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 7.4 प्रतिशत, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तुलना में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, अमरीका

सारणी 6.9 : अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर की विनिमय दर

माह/वर्ष	जीबीपी/अमरीकी डॉलर	यूरो/अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर/जापानी ये.	अमरीकी डॉलर/ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
1	2	3	4	5
मार्च 2009	1.4340	1.3308	98.100	0.6921
मार्च 2010	1.5082	1.3543	90.885	0.9095
अमरीकी डॉलर अधिमूल्यन (+) / अवमूल्यन (-) (मार्च 2009 अंत- मार्च 2010 अंत)	(-) 4.9	(-) 1.7	(-) 7.4	(-) 23.9
2010-11				
अप्रैल 2010	1.5324	1.3404	93.20	0.9263
मई 2010	1.4757	1.2693	91.51	0.8672
जून 2010	1.4738	1.2183	90.60	0.8671
जुलाई 2010	1.5298	1.2650	87.56	0.8694
अगस्त 2010	1.5732	1.2960	85.25	0.8998
सितम्बर 2010	1.5718	1.3642	83.48	0.9669
अक्टूबर 2010	1.6026	1.3921	80.49	0.9805
नवम्बर 2010	1.5558	1.2986	83.66	0.9590
दिसम्बर 2010	1.5602	1.3381	81.19	1.0235
अमरीकी डॉलर \$ अधिमूल्यन (+) / ह्रास (-) (मार्च 2010 अंत की तुलना में दिसम्बर 2010 के अंत में)	(-) 3.3	1.2	(-) 10.7	(-) 11.1

स्रोत : आरबीआई

में आर्थिक गतिविधि में तेजी और आर्थिक वृद्धि के अधिक अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण विशेष तौर से दिसम्बर, 2009 में मुख्य मुद्राओं की तुलना में कुछ शक्ति प्राप्त की। तथापि, मार्च, 2010 के अंत और दिसम्बर, 2010 के अंत के मध्य अमरीकी डॉलर 3.3 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 10.7 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तुलना में 11.1 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ जबकि यूरो की तुलना में 1.2 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई। यूरो की तुलना में मूल्य वृद्धि का कारण यूरो क्षेत्र के सदस्य देशों में से कुछ में सरकारी ऋण समस्याएं हो सकती हैं (सारणी 6.9)।

विदेशी ऋण

6.61 भारत का विदेशी ऋण स्टॉक 262.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,184,998 करोड़ रुपए) का स्तर मार्च 2009 के अंत की तुलना में 37.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2010 के अंत में 262.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,184,998 करोड़ रुपए) था। कुल वृद्धि में से दीर्घावधि ऋण 28.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अल्पावधि ऋण 9.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक अधिक था। अनुबन्ध 8.4 (क) और 8.4 (ख) मार्च 1991 से सितम्बर 2010 तक की अवधि का भारत का विदेशी ऋण क्रमशः भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर में भिन्न-भिन्न आंकड़े दर्शाते हैं।

6.62 सितम्बर, 2010 के अंत तक कुल विदेशी ऋण मार्च 2010 के अंत की तुलना में 33.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (12.8 प्रतिशत) से बढ़कर 295.8 बिलियन अमरीकी डॉलर (1,332,195 करोड़ रुपए) हो गया। भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण उच्च वाणिज्यिक उधार और अत्यावधिक ऋण हैं। इन्हें मिलाकर इन दोनों घटकों का योगदान भारत के विदेशी ऋण में कुल वृद्धि के 70 प्रतिशत से अधिक है। मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्यह्रास से उत्पन्न मूल्य प्रभाव का योगदान कुल वृद्धि में लगभग 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर में वृद्धि है। मूल्य प्रभाव को छोड़कर, विदेशी ऋण में वृद्धि 27.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हुई।

6.63 भारत के विदेशी ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधिक उधार के महत्व की ओर संकेत करता है। सितम्बर, 2010 के अंत में, 66.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के अल्पावधिक ऋण कुल विदेशी ऋण का 22.3 प्रतिशत था, जबकि शेष 77.7 प्रतिशत दीर्घावधिक ऋण था (सारणी 6.10)।

6.64 दीर्घावधिक घटक, जैसे वाणिज्यिक उधार, एनआरआई जमाराशियों और बहुपक्षीय उधार विदेशी ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनको मिलाकर, ये घटक सितम्बर, 2010 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 60.5 प्रतिशत होते हैं। जबकि शेष 17.2 प्रतिशत अन्य घटक (अर्थात् द्विपक्षीय उधार, निर्यात ऋण, और आईएमएफ और रुपया ऋण) हैं। वाणिज्यिक उधारों का हिस्सा

सारणी 6.10 : भारत का विदेशी ऋण स्टॉक						
माच अंत में	मिलियन अमरीकी डालर			करोड़ ₹		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	जोड़	दीर्घावधि	अल्पावधि	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
2005	116,279	17,723	134,002	508,777	77,528	586,305
2006	119,575	19,539	139,114	533,367	87,155	620,522
2007	144,230	28,130	172,360	628,771	122,631	751,402
2008	178,669	45,738	224,407	714,409	182,881	897,290
2009	181,185	43,362	224,547	923,044	220,907	1,143,951
2010 आं.सं.	209,873	52,471	262,344	948,168	236,830	1,184,998
2010 (जून अंत) आं.सं.	215,069	57,841	272,910	1,001,809	269,483	1,271,292
2010 (सित. अंत) त्व. अ.	229,837	66,010	295,847	1,035,647	296,548	1,332,195

स्रोत: वित्त मंत्रालय और भा.रि.बैं.

आं.सं. : आंशिक संशोधन; त्व.अ. : त्वरित अनुमान

सारणी 6.11 : विदेशी ऋण संघटन		(कुल विदेशी ऋण का प्रतिशत)			
क्र.सं.	संघटक	मार्च	मार्च	जून	सितम्बर
		2009 (आं.सं.)	2010 (आं.सं.)	2010 (आं.सं.)	2010 (त्व.अ.)
1	2	3	4	5	6
1	बहुपक्षीय	17.6	16.3	16.4	15.8
2	द्विपक्षीय	9.2	8.6	8.4	8.3
3	अमुको	0.5	2.3	2.2	2.1
4	निर्यात क्रेडिट	6.4	6.4	6.4	6.2
5	वाणिज्यिक उधारें	27.8	27.4	27.3	27.8
6	एनआरआई जमाराशियां	18.5	18.3	17.6	16.9
7	रुपया ऋण	0.7	0.6	0.6	0.6
8	दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	80.7	80.0	78.8	77.7
9	अल्पावधि ऋण	19.3	20.0	21.2	22.3
10	जोड़ विदेशी ऋण (8+9)	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: वित्त मंत्रालय और भा.रि.बैं.

आं.सं. : आंशिक संशोधन; त्व.अं. : त्वरित अनुमान

लगातार 27.8 प्रतिशत के साथ उच्चतम पर रहा और इसके बाद एनआरआई जमाराशियों (16.9 प्रतिशत) और बहुपक्षीय ऋण (15.8 प्रतिशत) हैं (सारणी 6.11)।

6.65 भारत के कुल विदेशी ऋण का मुद्रा संघटक दर्शाता है कि सितम्बर 2010 के अंत में कुल विदेशी ऋण 53.9 प्रतिशत अमरीकी डॉलर मूल्य वर्ग ऋण में है और इसके बाद भारतीय रुपया (18.8 प्रतिशत) जापानी येन (11.8 प्रतिशत), एसडीआर

(9.8 प्रतिशत) और यूरो (3.6 प्रतिशत) का स्थान आता है। सरकारी ऋण का मुद्रा संघटन एसडीआर मूल्य वर्ग ऋण (39.9 प्रतिशत) की प्रधानता दर्शाता है जो आईडीए से उधार, बहुपक्षीय एजेन्सियों के तहत विश्व बैंक की सुलभ ऋण व्यवस्था और आईएमएफ से एसडीआर आबंटन के कारण है। अमरीकी डॉलर-मूल्यवर्ग ऋण का हिस्सा सितम्बर, 2010 के अंत में 28.1 प्रतिशत और इसके बाद जापान से उधार के कारण जापानी मूल्य वर्ग (19.4 प्रतिशत) में है। (सारणी 6.12)

सारणी 6.12 : भारत के विदेशी ऋण और सम्प्रभु विदेशी ऋण का मुद्रा संघटक

क्र. सं.	मुद्रा	कुल विदेशी ऋण				सम्प्रभु विदेशी ऋण			
		मार्च 2009	मार्च 2010 ^{आ.सं.}	जून 2010 ^{आ.सं.}	सित. 2010 ^{त्व.अ.}	मार्च 2009 ^{आ.सं.}	मार्च 2010 ^{आ.सं.}	जून 2010 ^{आ.सं.}	सित. 2010 ^{त्व.अ.}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अमरीकी डालर	54.1	53.4	54.9	53.9	29.6	26.5	28.8	28.1
2	एसडीआर	9.8	10.7	10.1	9.8	39.5	41.7	39.8	39.9
3	भारतीय रुपया	15.4	18.6	18.1	18.8	5.7	8.9	8.9	8.6
4	जापानी येन	14.3	11.4	11.5	11.8	19.9	18.6	18.7	19.4
5	यूरो	4.1	3.6	3.3	3.6	5.2	4.3	3.8	4.0
6	पाउंड स्टर्लिंग	2.0	1.8	1.7	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0
7	अन्य	0.3	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: वित्त मंत्रालय और भार.रि.बैं. आं. सं. : आंशिक संशोधित त्व.अ. त्वरित अनुमान

6.66 भारत के विदेशी ऋण संघटन में दीर्घावधि ऋण में गिरावटी प्रवृत्ति दर्शाते हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संघटकों दोनों के हिस्सों के साथ पिछले वर्षों से बदलाव आया है। भारत के विदेशी कुल ऋण में निजी भागीदारों का हिस्सा रहा है। सरकारी (सम्प्रभु) विदेशी ऋण सितम्बर, 2010 के अंत में 72.3 था जबकि गैर सरकारी ऋण 223.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था। कुल विदेशी ऋण में सरकारी ऋण का हिस्सा मार्च 2010 के अंत में 25.6 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2010 के अंत तक

24.4 प्रतिशत रह गया। सरकारी विदेशी ऋण और सघट का अनुपात पिछले चार वर्षों में लगभग 5.0 प्रतिशत रहा है।

6.67 सम्प्रभु विदेशी ऋण भारत सरकार के समग्र लोक ऋण का छोटा भाग है। सम्प्रभु ऋण का अधिकांश भाग घरेलू स्रोत है। घरेलू ऋण श्रेणी में भी दिनांकित प्रतिभूतियों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो वाणिज्यिक और सहकारी बैंक और बीमा कंपनियों के स्वामित्वाधीन हैं। लोक ऋण के लिए हुए संघटन और इस तथ्य को देखते हुए कि बैंकिंग और बीमा का काफी

बॉक्स 6.2 : भारत का सम्प्रभु ऋण: विशिष्ट लक्षण

मार्च 2010 के अंत में (तेरहवें वित्त आयोग) के अनुसार सघट के 78.8 प्रतिशत के समेकित ऋण (केन्द्र और राज्य) के साथ लोक ऋण स्तर के बारे में चिंताएं बनी रही। लोक ऋण के स्तर का निर्धारण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संघटन, पुनर्वित्तपोषण आवश्यकताओं और निवेश आधार पर एक दृष्टि डाली जाए। निम्नलिखित मुद्दे केन्द्र सरकार के लोक ऋण के विशिष्ट लक्षणों को दर्शाते हैं जो इसे कई उन्नत देशों के अनुभव के अनुसार कम बाजार जोखिमों से कम असुरक्षित बनाकर विशिष्ट श्रेणी में लाते हैं।

- कुल लोक ऋण में सम्प्रभु विदेशी ऋण का हिस्सा सितम्बर, 2010 के अंत में 10.8 प्रतिशत था। ऋण का अधिकांश भाग कुल लोक ऋण के 1 प्रतिशत से कम वाले सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेश सहित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय क्रेडिटर्स थे। चूंकि भारत की पहुंच अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में एक सम्प्रभु संस्था के रूप में नहीं है, अतः विदेशी वाणिज्यिक निवेशकों के कारण पुनर्वित्त जोखिम जिसने यूरो क्षेत्र सम्प्रभु ऋण संकट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह पूर्णतया गायब है।
- घरेलू ऋण कुल केन्द्रीय सरकार सम्प्रभु ऋण का 89.2 प्रतिशत है। इसमें से 11.5 प्रतिशत अविश्रय श्रेणियां जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी प्रतिभूतियां हैं, शेष 77.7 प्रतिशत विक्रय प्रतिभूतियां दिनांकित प्रतिभूतियां (दीर्घावधि) में 73.4 प्रतिशत और राजकोषीय ढुंढियों (अल्पावधि) में 4.3 प्रतिशत सहित हैं;
- दिनांकित प्रतिभूतियों की श्रेणी में कुल ऋण का बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) के सम्बन्ध में 51.9 प्रतिशत और बीमा कंपनियों (मुख्यतः जीवन बीमा निगम) के सम्बन्ध में 22 प्रतिशत हिस्सा है। बैंकों के लिए आवश्यक सांविधिक द्रवता अनुपात (एसएलआर) हुए और यह तथ्य कि बैंकों और बीमा का महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र में आता है जो पुनर्वित्त पोषण जोखिम न्यूनतम और सर्वोत्तम है।
- केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की औसत परिपक्वता 10 वर्ष है जो इसे पुनर्वित्त जोखिम से कम असुरक्षित बनाती है।

इस तथ्य के बावजूद कि सम्प्रभु ऋण में न्यूनतम वित्त पोषण और बराबर जोखिम होता है फिर भी राजकोषीय लक्ष्यों और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जो भारत सरकार के वार्षिक बजट के भाग हैं, के माध्यम से स्थाई बेंचमार्क तक लोक ऋण स्तरों को कम करने के संयुक्त प्रयास जारी हैं।

सारणी 6.13 : भारत के मुख्य विदेशी ऋण संकेतक (प्रतिशत)

वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	जीडीपी की तुलना में कुल विदेशी ऋण	ऋण शोधन अनुपात	कुल विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी प्रारक्षित निधियां	कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण	विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि विदेशी ऋण* का अनुपात	कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि विदेशी ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	83.8	28.7	35.3	7.0	45.9	146.5	10.2
1995-96	93.7	26.9	26.2	23.1	44.7	23.2	5.4
2000-01	101.3	22.5	16.6	41.7	35.4	8.6	3.6
2005-06	139.1	16.8	10.1#	109.0	28.4	12.9	14.0
2006-07	172.4	17.5	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2007-08	224.4	18.0	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2008-09	224.5	20.5	4.4	112.1	18.7	17.2	19.3
2009-10PR	262.3	18.1	5.5	106.4	16.7	18.8	20.0
जून 2010 के अंत में आंस.	272.9	-	3.9	101.0	15.9	21.0	21.2
सित. 2010 के अंत में त्व.अ.	295.8	-	3.8	99.0	15.6	22.5	22.3

स्रोत: वित्त मंत्रालय और भारिबैं आंसं. : आंशिक रूप से संशोधित त्व.अ. : त्वरित अनुपात

- खंडित अवधि हेतु नहीं निकाले गए हैं।

*अल्पावधि ऋण मूल रूप से परिपक्वता पर आधारित है

भारत सहस्राब्दी जमा राशियों की 7.1 बिलियन अमरीकी डालर की पुनःअदायगी और 23.5 मिलियन अमरीकी डालर की पूर्व अदायगी को छोड़कर 6.3 प्रतिशत निकाला गया।

@ ऋण शोधन अनुपात विदेशी चालू प्राप्तियों (सरकारी अन्तरणों का निवल) से सम्बद्ध सकल ऋणशोधन भुगतानों का अनुपात है।

हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र में है, पुनिर्वितीयन जोखिम जो यूरो क्षेत्र संकट के मूल में रहा है, अत्यधिक है। (बॉक्स 6.2)

6.68 मुख्य ऋण संकेतक दर्शाते हैं कि भारत का विदेशी ऋण और सघउ अनुपात 18.1 प्रतिशत (2008-09 में 20.5 प्रतिशत) और 2009-10 के दौरान ऋण सेवा अनुपात 5.5 प्रतिशत (2008-09 में 4.4 प्रतिशत) था। भारत के विदेशी विनिमय प्रारक्षित भंडारों ने सितम्बर 2010 में विदेशी ऋण स्टॉक के लिए 99 प्रतिशत (मार्च 2010 के अंत में 106.4 प्रतिशत) कवर उपलब्ध कराया। सितम्बर 2010 के अंत में अल्पावधिक विदेशी ऋण और विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधियों का अनुपात मार्च 2010 के अंत में 18.8 प्रतिशत की तुलना में 22.5 प्रतिशत था। रियायती ऋण और कुल विदेशी ऋण का अनुपात निरन्तर गिरता रहा और यह मार्च 2010 के अंत में 16.7 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर 2010 के अंत में 15.6 प्रतिशत हो गया। मुख्य विदेशी ऋण संकेतक सारणी 6.13 में प्रदर्शित हैं।

6.69 भारत सरकार की विदेशी ऋण प्रबन्धन नीति, अंत उपयोग और सर्वांग लागत प्रतिबन्धों के माध्यम से ईसीबी को विनियमित करते हुए, एनआरआई जमाराशियों पर ब्याज दरों को

यौक्तिकीकरण करते हुए और दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण को मॉनिटर करते हुए दीर्घावधि परिपक्वताओं सहित रियायती शर्तों पर सम्प्रभु ऋण जुटाने पर लगातार ध्यान केन्द्रित कर रही है।

अन्तरराष्ट्रीय तुलना

6.70 विश्व बैंक की वैश्विक विकास वित्त, 2010 में दिए आंकड़ों के अनुसार बीस सबसे अधिक ऋणग्रस्त विकासशील देशों के विदेशी ऋण की अन्तरराष्ट्रीय तुलना दर्शाती है कि भारत विदेशी ऋण स्टॉक के सन्दर्भ में 2008 में रूसी संघ, चीन, टर्की और ब्राजील के बाद पांचवा सबसे बड़ा ऋणग्रस्त देश था। भारत के विदेशी ऋण स्टॉक और सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का 2008 में अनुपात चौथा न्यूनतम 19.0 प्रतिशत था, जबकि चीन का 8.7 प्रतिशत पर न्यूनतम अनुपात था। भारत का विदेशी ऋण पोर्टफोलियो में रियायती तत्व पाकिस्तान, इन्डोनेशिया और फिलीपिंस के बाद चौथा अधिकतम है (सारणी 6.14)

6.71 विदेशी ऋण प्रारक्षित निधियों द्वारा प्रदत्त विदेशी ऋण के कवर के सन्दर्भ में, भारत की स्थिति चीन, थाईलैण्ड और

सारणी 6.14 : शीर्ष 20 ऋण प्राप्तकर्ता विकासशील देश 2008 की अंतरराष्ट्रीय तुलना

क्र. सं.	देश	कुल विदेशी ऋण का स्टॉक (मिलियन अमरीकी डॉलर)	सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल ऋण (प्रतिशत)	कुल विदेशी ऋण की तुलना अल्पावधि ऋण (प्रतिशत)	कुल ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार (प्रतिशत)	कुल विदेशी ऋण की तुलना में रियायती ऋण (प्रतिशत)
1	रूसी संघ	402,453	25.8	13.6	106.1	0.5
2	चीन	378,245	8.7	49.5	514.5*	10.8
3	तुर्की	277,277	35.3	18.3	26.6	2.7
4	ब्राजील	255,614	16.2	14.3	75.8	1.4
5	भारत	230,611	19.0	19.6	111.6	20.5
6	पोलैंड	218,022	42.1	29.8	28.5	0.2
7	मेक्सिको	203,984	19.1	12.0	46.7	0.5
8	इंडोनेशिया	150,851	30.4	17.6	34.2	27.9
9	अर्जेंटिना	128,285	39.9	29.2	36.2	1.6
10	कजाखिस्तान	107,595	95.0	9.9	18.5	1.1
11	रोमानिया	104,943	54.7	29.7	37.9	1.5
12	यूक्रेन	92,479	51.7	22.1	34.1	1.6
13	मलेशिया	66,182	35.1	34.5	139.3	6.5
14	फिलिपीन्स	64,856	35.0	10.8	57.8	23.1
15	थाइलैंड	64,798	32.0	37.4	171.3	11.1
16	चिली	64,277	41.3	23.2	35.9	0.3
17	वेनेजुएला	50,229	16.0	33.8	85.7	1.0
18	पाकिस्तान	49,337	28.7	2.8	18.3	60.6
19	कोलम्बिया	46,887	20.2	12.1	50.5	2.1
20	लातविया	42,108	127.3	33.5	12.5	0.3

स्रोत : वर्ल्ड बैंक ग्लोबल डिवलपमेंट फाइनेंस, 2010

*: विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के आंकड़े स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ चाइना से लिए गए हैं।
टिप्पणी : सारणी में कॉलम सं. 3 में प्रस्तुत ऋण की मात्रा के आधार पर देशों को क्रमबद्ध किया गया है।

मलेशिया के बाद 111.6 प्रतिशत पर चौथे स्थान पर है। बाह्य देशों के कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण हिस्से की एक तुलना से स्पष्ट होता है कि भारत की स्थिति दसवीं न्यूनतम थी जबकि पाकिस्तान का अनुपात न्यूनतम था।

जी-20

6.72 जी-20 की स्थापना 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों ने मिलकर की। अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना की मजबूती में योगदान देकर और राष्ट्रीय नीतियों, अन्तरराष्ट्रीय सहयोगों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों संबंधी चर्चा को अवसर प्रदान कर, जी-20 विश्व में विकास, वित्तीय स्थायित्व और विकास में मदद करता है।

6.73 अपने प्रारंभ से ही, जी-20 वित्त मंत्रियों और सेन्ट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकें आयोजित कीं और विश्व में वित्तीय स्थायित्व संवर्धन के उपायों को प्रोत्साहन देने तथा सतत आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने हेतु चर्चा की।

6.74 2008 में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के समय, जी-20 के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। वैश्विक मुद्दों के संचालन के लिए मंच के रूप में जी-8 को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए 2009 में अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में नामित किया गया था। यह कार्रवाई वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना गया क्योंकि इस मंच में उभरती और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं दोनों हैं, अतः यह अधिक समावेशी है। (बॉक्स 6.3)

6.75 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) के कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत जी-20 के आदेश पर हुई जिससे

बॉक्स 6.3 : जी-20: मूल तथ्य

- ❖ जी-20 में 19 देश है अर्थात अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ जिसका प्रतिनिधित्व 20वें सदस्य के रूप में काउंसिल प्रेजिडेंसी और यूरोपीयन सेन्ट्रल बैंक बारी-बारी से करते हैं।
- ❖ यह वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 90 प्रतिशत, विश्व व्यापार का 80 प्रतिशत और विश्व जनसंख्या के दो-तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
- ❖ 2008 में वैश्विक संकट के प्रादुर्भाव के बाद जी 20 के नेताओं अथवा राष्ट्राध्यक्षों के पांच शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।

क्र.स.सम्मेलन	स्थल	माह/वर्ष
1	वॉशिंगटन डीसी, अमरीका	15 नवम्बर, 2008
2	लंदन, यूके	2 अप्रैल, 2009
3	पिट्सबर्ग, अमरीका	24-25 सितम्बर 2009
4	टोरंटो, कनाडा	26-27 जून 2010
5	सिओल, दक्षिण कोरिया	11-12 नवम्बर 2010

- ❖ अगला जी-20 सम्मेलन 3-4 नवम्बर, 2011 को फ्रांस के कान में होगा।

बाक्स 6.4 : भारत और जी-20

भारत जी 20 का सदस्य तब से बना, जब इसकी स्थापना 1999 में वित्त मंत्री मंच के रूप में हुई। भारत दक्षिण एशिया से एकमात्र जी-20 का सदस्य देश है और जी-20 में महत्वपूर्ण उभरते बाजार सदस्य देशों में से एक है।

जी-20 में भारत के आर्थिक संकट की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- ❖ भारत 2002 में जी-20 का अध्यक्ष था और उसने 2002 में जी-20 वित्त मंत्रियों और सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक की मेजबानी भी की।
- ❖ भारत (भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर) ने वृद्धिशील ध्वनि विनियमन और सशक्त पारदर्शिता (नवम्बर 2008 वाशिंगटन सम्मेलन के बाद) सम्बन्धी जी-20 कार्यदल की सह अध्यक्षता की।
- ❖ भारत वर्तमान में कनाडा के साथ सशक्त सतत और संतुलित वृद्धि के जी-20 फ्रेमवर्क सम्बन्धी कार्यदल का सह-अध्यक्ष है।
- ❖ भारत विभिन्न विषयक मुद्दों पर जी-20 में विकासशील देशों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो निम्नलिखित हैं:
 - ✓ वित्तीय क्षेत्र नियामक सुधार
 - ✓ जलवायु परिवर्तन
 - ✓ अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सुधार
 - ✓ वृद्धि और राजकोषीय समेकन
 - ✓ वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) और आईएसबी जैसे मंचों में शेरधारिता में वृद्धि
 - ✓ असहकारी क्षेत्राधिकार (वैश्विक मंच, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ आदि) संबंधी मुद्दे।

कि वैश्विक संस्थानों की कार्य प्रणाली और वैश्विक शासन संरचना में मूलभूत परिवर्तन की आशा पूर्ण हुई। जी-20 के सदस्य के रूप में भारत वैश्विक आर्थिक शासन और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में सक्रिय रहा है (बॉक्स 6.4)।

जी-20 सम्मेलनों के मुख्य मुद्दे/परिणाम

6.76 वैश्विक आर्थिक संकट को सबसे अधिक संगठित प्रत्युत्तर जी-20 देशों के मंच से आया था। जी-20 के नेताओं के शिखर सम्मेलनों ने संकट से उबरने के लिए अल्प और मध्यावधि दोनों कार्रवाईयों की आवर्ती एजेंडा निर्धारित किया गया है।

6.77 जी-20 का पहला शिखर सम्मेलन युद्ध-पश्च युग में सबसे बड़े वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में नवम्बर 2008 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। इसकी विशेष उपलब्धियों में, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय नियमन को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताओं का निर्माण, वित्तीय स्थायित्व मंच और अन्य मुख्य मानक-निर्धारण निकायों का विस्तार; अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में उभरते और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को प्रबल स्वर प्रदान करना था।

6.78 चार माह बाद, जी-20 नेता अप्रैल 2009 में लंदन में पुनः मिले, जिसमें उन्होंने विश्वास बहाली, वृद्धि और कार्य बहाली, वैश्विक व्यापार और निवेश संवर्धन और संरक्षणवाद को अस्वीकार करने की प्रतिज्ञा ली। वे अप्रत्याशित और संगठित राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक आसानी के लिए भी सहमत हुए तथा अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त संसाधनों को प्रदान करने का समझौता हुआ जिसमें से 750 बिलियन अमरीकी डालर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए थे।

6.79 जी-20 के नेताओं का तीसरा शिखर सम्मेलन 24-25 सितम्बर 2009 को पिट्सबर्ग अमरीका में हुआ था। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित से संबंधित थे: (क) विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपनी आवाज उठाने और कोटा सुधार के लिए समय सीमा (ख) वित्तीय क्षेत्र में नियामक सुधार के लिए समय सीमा (ग) सशक्त सतत और संतुलित वृद्धि फ्रेमवर्क की शुरुआत (घ) सर्वाधिक गरीबों के हितों की सुरक्षा करते हुए अदक्ष जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त और यौक्तिकीकरण का संकल्प लेना तथा (ङ) आर्थिक मुद्दों संबंधी सहकारिता के लिए जी-20 प्रधान बहुपक्षीय मंच को नामित करना।

6.80 जी-20 नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन 26-27 जून 2010 को टोरंटो, कनाडा में आयोजित हुआ था। वैश्विक आर्थिक संकट हल करने में जी-20 की उपलब्धियां बढ़ते हुए, नेता अगले कदमों पर सहमत हुए कि जी-20 देशों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार कार्यों के साथ वृद्धि की पूर्ण वापसी, वृद्धि अनुकूल राजकोषीय समेकन का पालन, वित्तीय प्रणालियों में सुधार और सशक्तिकरण और मजबूत सतत और संतुलित वैश्विक वृद्धि का

सृजन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं राजकोषीय योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध थीं जो 2013 तक घाटे को कम से कम आधा कर देंगी और 2016 तक सरकारी ऋण और सघट अनुपात स्थिर अथवा कम कर देंगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पर समझौते हुए (i) सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को सशक्त बनाना, कम्पनी शासन सुधार में वृद्धि, वित्तीय बाजार विकास, अवसंरचना प्रसार कुछ उभरते बाजारों में बड़ी विनिमय दर लोचशीलता; (ii) विकास परिदृश्य में वृद्धि और उसे बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण जी-20 सदस्यता वाले देशों में ढांचागत सुधारों का अनुकरण; और (iii) वैश्विक मांग के पुनः संतुलन संबंधी अधिक प्रगति करना। नेता तीन वर्ष (2013 के अंत तक) तक पुनर्नवीकरण के लिए भी सहमत हो गए जिसमें प्रतिबंधों को हटाने से बचना अथवा माल और सेवा में व्यापार पर नए प्रतिबंध लगाना, नए निर्यात प्रतिबंधों को लागू करना, अथवा निर्यात बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के असंगत उपायों को कार्यान्वित करना

शामिल है। इसके अलावा, नेता दोहा विकास राउंड के लिए यथासंभव संतुलित और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के समर्थन पर भी सहमत हो गए।

6.81 जी-20 का पांचवा शिखर सम्मेलन 11 और 12 नवम्बर 2010 को सिओल दक्षिण कोरिया में हुआ। यह सम्मेलन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनः संतुलन का निर्देश भी हो सकता है। पहले के जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक ने बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणालियों, जो आर्थिक मौलिक तत्वों को दर्शाता है और मुद्राओं की प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन से बचाता है, की ओर रुख करने की प्रतिज्ञा लेकर संभावित मुद्रा विवाद की चिंता को हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की (बाक्स 6.5)

बाँक्स 6.5 : नवम्बर 2010 में सिओल, दक्षिण कोरिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के नेताओं की घोषणा के मुख्य बिन्दु

- सिओल कार्रवाई योजना धारण में सशक्त सतत् और संतुलित वृद्धि के साझा हितों के नजदीक पहुंचने के लिए देश विशेष की कार्रवाईयों शामिल हैं। योजना में निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है:
 - (क) अधिक बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणालियों की ओर मुड़ना और मुद्राओं की प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन से बचने की दिशा में चालू सुधार और सतत् वृद्धि और वित्तीय बाजारों में स्थिरता की वृद्धि सुनिश्चित करने की राजकोषीय समेकन सहित वृहत आर्थिक नीतियों को अपनाना। प्रारंभिक मुद्राओं सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विनिमय दरों की अतिरिक्त अस्थिरता और अव्यवस्थित हलचल के प्रति सतर्क रहेंगे;
 - (ख) ढांचागत सुधारों की श्रेणी का कार्यान्वित करना जो वैश्विक मांग को बढ़ावा देता है और उसे बनाए रखता है, रोजगार सृजन करता है, तथा विकास की संभावना को बढ़ाता है; तथा
 - (ग) विदेशी स्थायित्व संवर्धन के लिए पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (एमएपी) को बढ़ावा देना। विदेशी सतत संवर्धन के लिए और अतिरिक्त असंतुलनों को घटाने और सतत स्तरों पर चालू लेखा असंतुलनों को बनाए रखने में सहायक नीतियों की पूर्ण श्रेणी का अनुकरण करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए नेताओं ने जी-20 फ्रेमवर्क कार्यदल (जिसका भारत कनाडा के साथ सह-अध्यक्ष है) पर कार्य किया है जिसमें संकेतकों से बनी निर्देशात्मक दिशा-निर्देशों के विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की तकनीकी सहायता मिली। ये संकेतक बड़े असंतुलनों जिन्हें रोकने और जिन पर उपचारात्मक कार्रवाई की जानी है, समय पर पहचान को सुकर बनाने के लिए एक कार्य प्रणाली का काम करेंगे। फिर निर्देशात्मक दिशा निर्देशों को जी-20 के वित्त मंत्रियों और सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों को उनकी अप्रैल 2011 की मंत्रिमंडलीय बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- सिओल विकास सर्वसम्मति धारण एक बहुपक्षीय कार्य योजना और अवसंरचना संबंधी उच्चस्तरीय पेनल (एचएलपी) की स्थापना सहित छह सिद्धांतों (आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रण, वैश्विक विकास साझेदारी, वैश्विक अथवा क्षेत्रीय सर्वांगी मुद्दे, निजी क्षेत्र की भागीदारी, पूरकता, और परिणामोन्मुखी) और नौ स्तम्भों (अवसंरचना, एचआरडी, व्यापार, रोजगार सृजन में निजी निवेश, वित्तीय समावेशन, लचीलेपन के साथ विकास, खाद्य सुरक्षा, शासन, और ज्ञान की साझेदारी) पर आधारित था।
- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्रों के लिए आईएमएफ के नए लिखतों का पृष्ठांकन और क्षेत्रीय वित्तीय के नए लिखतों का पृष्ठांकन और क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं (आरएफए) के साथ कार्य सहित, सर्वांगी प्रकृति के आघातों से निपटने के लिए सुधरती वैश्विक क्षमता पर हाल ही में आईएमएफ के कार्य का पृष्ठांकन। यह अन्यों में अस्थिर पूंजी प्रवाहों के प्रत्युत्तर के रूप में वृहत विवेकपूर्ण उपायों का भी पृष्ठांकन किया।
- कम प्रतिनिधित्व, उभरते बाजार और विकासशील देशों (ईएफडीसी) के पक्ष में कोटा में 6 प्रतिशत अन्तरण के आईएमएफ सुधारों संबंधी गिओंगजू जी-20 वित्तमंत्री और सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों के समझौते का पृष्ठांकन तथा ईएमडीसी के आर्थिक भागों को बेहतर दर्शाने के लिए 2013 तक कोटा फॉर्मूला की व्यापक समीक्षा और जनवरी 2014 तक कोटा की अगली सामान्य समीक्षा पूरी करना।
- नए वित्तीय विनियामक पूंजी और नकदी फ्रेमवर्क (बासेल III) के मुख्य तत्वों और एसआईएफआई जिस पर कार्य जारी रहेगा को बेहतर विनियमित करने के उपायों का पृष्ठांकन। यह वृहत विवेकी नीति, फ्रेमवर्क, सेडो बैंकिंग का सशक्तन, विनियमन और निरीक्षण तथा जिसों वाले व्युत्पन्न बाजारों को नियंत्रित करने पर आगे कार्य करने पर भी सहमति हुई थी।
- इस बात की पहचान करते हुए कि दोहा विकास दौर का निष्कर्ष निकालने की प्रतिज्ञा दुहराने हेतु 2011 एक महत्वपूर्ण अवसर है, संरक्षणवाद के सभी रूपों के प्रतिरोध के लिए पुनःप्रतिबद्धता लेना।
- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई योजना को आत्मसात करना।

चुनौतियां

6.82 कई उन्नत देशों में उच्च राजकोषीय और लोक ऋण के साथ परिधीय यूरो-जोन देशों में अनवरत संप्रभु ऋण जोखिम और इस बात का डर कि यह वित्तीय क्षेत्र तक फैल सकता था, वैश्विक सुधार के लिए एक जोखिम है। संकट के शुरुआत में ही, पूंजी प्रवाहों के विपर्यय और निर्यातों में गिरावटों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है।

6.83 द्वितीय, नाजुक वैश्विक सुधार और जोरदार घरेलू वृद्धि से 2009-10 और 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) में उच्च व्यापार और चालू लेखा घाटा हुआ, जो कुछ चिंता का विषय है। यह समस्या अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोतरी से आगे और बढ़ सकती है।

6.84 तृतीय, पूंजी प्रवाहों के आवधिक बहाव से संपत्ति मूल्यों, मुद्रा अधिमूल्यन और मुद्रास्फीति में तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में अवशोषण क्षमता की समस्या हो सकती थी। पूंजी प्रवाहों में ऐसे बढ़ोतरी का प्रबन्धन करना चुनौतीपूर्ण है।

6.85 चतुर्थ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह जो स्थिर और उत्पादक रूप में हैं, 2008-09 में 37.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2009-10 में 33.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और चालू राजकोषीय वर्ष (नवम्बर 2010 तक) में 19.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। इसके अलावा, पूंजी अन्तर्प्रवाहों की बड़ी मात्रा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में है जो स्वरूप में अस्थिर है। पूंजी के अन्य रूपों की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने होंगे।